● वर्ष-3
● अंक-05
रायपुर, रविवार
13 अगस्त 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 13 अगस्त रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 15 अगस्त मंगलवार को प्रकाशित होगा।

बंगाल में हिंसा, अराजकता और जंगलराज

जेपी नड्डा ने कोलकाता में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के परिवारों से मुलाकात की

नईदिल्ली। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों और पंचायत चुनाव के पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। नड्डा ने कहा कि जब विपरित परिस्थिति में आपको जीत की बधाई देता हूं तो वहीं जिन लोगों ने इस पंचायत चुनाव में जान को आहुत किया, जिन्हें जान गंवानी पड़ी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारवालों को ताकत दें और जो बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता घायल हुए वो जल्दी ठीक होकर फिर से इस प्रजातंत्र और बंगाल की रक्षा के लिए आगे खड़े हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार का तांडव हम सभी ने पहले भी देखा था, जिस तरीके से प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया।

बंगाल में तांडव

नड्डा ने कहा कि आजाद भारत में ऐसा ही तांडव फिर हमने देखा है, ये शर्मनाक बात है, शर्म करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बंगाल ने अपना काफी योगदान दिया है। यहां से हमें धार्मिक नेता मिले, जिन्होंने देश को दिशा दी। यहां से सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाले नेता मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कला जगत को दिशा देने वाला नेतृत्व बंगाल से मिला। भाषा, संस्कृति को एक रूप देने वाला बंगाल से मिला। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज बंगाल मुसीबत से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा, अराजकता और जंगलराज है...और ममता दीदी दुनिया भर में खुद को लोकतंत्र की चैंपियन के रूप में प्रदर्शित करती फिरती हैं।

भाजपा जीतेगी

जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वही ममता दीदी ने प्रजातंत्र को मारने का काम किया है, प्रजातंत्र की गला घोंटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी प्रगति कर रहा है। आज, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है... और मोदी जी के अपने प्रधानमंत्रित्व के तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ममता जी सुन लो...आप हमें जितना दबाओगे, हम उतने ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। पिछले लोकसभा में यहां की जनता ने हमें 18 सीटें दी थी, इस बार 2024 में 35 से ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे।

टीएमसी का आरोप, हिंसा में भाजपा के गुंडे शामिल थे

तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जुलाई में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि भाजपा के ''गुंडे'' शामिल थे। टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री के आरोप को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को उसके वित्तीय बकाये से वंचित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने भाजपा की पंचायती राज परिषद को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए पंचायत चुनाव के दौरान विपक्ष को डराने के लिए ''आतंक का माहौल बनाने और धमकियां देने'' को लेकर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की आलोचना की थी। पांजा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, ''क्या इसलिए कि भाजपा पंचायत चुनाव नहीं जीत सकी, आतंक और धमकी का आरोप लगाया जा रहा है? यह भाजपा है, जिसने पश्चिम बंगाल में हिंसा की।'' राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पांजा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ''उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं।'' अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वॉकआउट करने के लिए प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा, ''मणिपुर पर आपके बोलने के लिए विपक्ष का संसद से वॉकआउट करना जरूरी था।''

सांसदी लौटने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे राहुल गांधी

नईदिल्ली। लोकसभा सदस्यता वापस पाने के बाद वायनाड में अपनी पहली सार्वजनिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड उनका परिवार है और भाजपा और आरएसएस यह नहीं समझते कि परिवार कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस नहीं समझते कि परिवार क्या होता है। वे यह नहीं समझते कि जितना अधिक वे आपको और मुझे अलग करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही करीब आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे सोचते हैं कि अगर हम राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करते हैं, वायनाड के साथ उनका रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करते हैं, तो वायनाड के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।

सरकार पर निशाना

मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आप (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) भारत माता की हत्या के बारे में बात करने में दो मिनट बिताते हैं। आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आप भारत के विचार का अनादर कैसे कर सकते हैं? आप वहां क्यों नहीं गए? आपने हिंसा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कोई भी भारत के विचार की हत्या करता है वह राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि हर जगह खून है, हर जगह हत्या है, हर जगह बलात्कार है। मणिपुर में यही स्थिति है और प्रधानमंत्री ने संसद में 2 घंटे, 13 मिनट तक बात की, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट ही बात की। वह हँसे, मज़ाक किया। उनका मंत्रिमंडल हँसा, मज़ाक किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर में हजारों लोग हैं जिन्होंने यह झेला है।

सर्जिकल स्ट्राइक से ही दूर होगी मणिपुर की समस्या?

राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद के बीच कि सेना मणिपुर में स्थिति को दो दिनों में नियंत्रित कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आपत्ति जताई, एनपीपी नेता एम रामेश्वर सिंह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्रभावी कार्रवाई मणिपुर में किए जाने की बात कही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी है। एम रामेश्वर सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से यह भी अनुरोध किया था कि कुछ एजेंसियां जो कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उसमें कहा गया है कि सभी कुकी आतंकवादी अब शिविरों में हैं और सभी हथियार उनके पास हैं। तो अब मणिपुर के लोगों को यह शंका सताने लगी है कि आखिर आग कहां से आ रही है। दूसरी तरफ से कौन फायरिंग कर रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री के बयानों से यह स्पष्ट है कि सीमा पार से कुछ अवैध अप्रवासी, अवैध कुकी उग्रवादी आ रहे हैं। और वह कहते रहे हैं कि इसमें बाहरी आक्रामकता शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि न केवल मणिपुर के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ प्रभावी, प्रभावकारी किया जाना चाहिए ताकि समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। यह बयान राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद के बीच आया है।

बरनाला में मस्जिद बनाने के लिए एक साथ आए हिंदू-सिख

नईदिल्ली। भारत 15 अगस्त को आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। पंजाब के बरनाला के कुटबा बहमनिया गांव में खुशी का माहौल है। विविधता में एकता का असली सार यहां सबसे अधिक चमकता है। गाँव के शांत माहौल में शुक्रवार की नमाज़, अज़ान की आवाज़ गूँजती है और इसके बीच, नासिर मस्जिद, जिसे हाल ही में बहाल किया गया था, एक विभाजन-पूर्व मस्जिद के रूप में खड़ी है। कुटबा बहमनिया के सरपंच (ग्राम प्रधान) बूटा सिंह ने गांव की पहली मस्जिद का उद्घाटन देखा, क्योंकि विभाजन के बाद मूल मस्जिद अनुपयोगी हो गई थी, मुस्लिम आबादी के पाकिस्तान चले जाने के कारण केवल चार परिवार बचे थे। विशेष रूप से मस्जिद एक गुरुद्वारे के निकट स्थित है।

सिंह बताते हैं कि हम गुरुद्वारा परिसर के अंदर मस्जिद और पीर की मजार की देखभाल करते थे। लेकिन हमने पैसे इकट्ठा करने और मस्जिद का नवीनीकरण करने का फैसला किया, जो फिर से उपयोग में आ गया है। एक महिला, जिसके पिता ने विभाजन के दौरान मुस्लिम ग्रामीणों को पलायन करते देखा था, अपनी राहत व्यक्त करते हुए कहती है कि इतिहास बहाल हो गया है। मुझे खुशी है कि गांव में सभी समुदाय एक साथ रहते हैं। मोहम्मद तारिक इस बात पर जोर देते हैं कि पूरा समुदाय महत्वपूर्ण अवसरों पर एकजुट होता है। ऐसे राज्य में जहां आजादी के समय मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत से घटकर आज 1.93 प्रतिशत रह गई है, ग्रामीण आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जेबें खोल रहे हैं, और कभी-कभी तो गुरुद्वारे भी, परित्यक्त मस्जिदों को बहाल करने में मदद कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 160 से अधिक मस्जिदों का जीर्णोद्धार किया गया है। कुछ किलोमीटर दूर, बरनाला जिले के बखतगढ़ गांव में, एक मस्जिद निर्माणाधीन है। 46 वर्षीय किसान अमनदीप सिंह ने 2022 में मस्जिद के निर्माण के लिए उदारतापूर्वक 250 वर्ग गज जमीन दान में दी। उनके परोपकारी भाव के बारे में सुनकर, गाँव के समुदाय एक साथ आए और आज मस्जिद पूरी होने वाली है। अमनदीप बताते हैं कि हमारे पास पर्याप्त ज़मीन और संपत्ति है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रायपुर शहर को 132 करोड़ 42 लाख रुपये के कई विकास कार्यो की सौगात दी। श्री बघेल ने रायपुर शहर के बीच ऐतिहासिक जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख समाचार

अनवर उल हक बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

पाकिस्तान: बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पाकिस्तानी सीनेटर अनवारुल हक काकर को विधानसभा भंग होने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से शनिवार को कार्यवाहक पीएम के तौर पर कक्कड़ के नाम की घोषणा की गई। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज के बीच शनिवार को एक बैठक में कक्कड़ के नाम पर सहमति बनी। 9 अगस्त को आम चुनाव के लिए मंच तैयार करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया गया था, जिसमें पूर्व पीएम इमरान खान भाग नहीं ले पाएंगे। नियमों के मुताबिक विधानसभा भंग होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होगा। पाकिस्तान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं लेकिन परिसीमन के बाद नई जनगणना के नतीजों को निवर्तमान सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे चुनाव से पहले परिसीमन करना एक संवैधानिक दायित्व बन गया है। अनवारुल हक मार्च 2018 से पाकिस्तान की सीनेट के सदस्य हैं। अनवर 2018 में बलूचिस्तान से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे।

झारखंड में होने वाले उपचुनाव में संयुक्त प्रचार करेगा 'इंडिया'

नईदिल्ली। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की झारखंड इकाई डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के मकसद से संयुक्त रूप से प्रचार करेगा। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। गठबंधन ने उपचुनाव के लिए बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है, जो 17 अगस्त को पर्चा दाखिल करेंगी। बेबी झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की पत्नी और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की नेता हैं। उपचुनाव पांच सितंबर को होगा, जबकि मतगणना आठ सितंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। डुमरी उपचुनाव को लेकर 'इंडिया' की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में डुमरी उपचुनाव को लेकर 'इंडिया' गठबंधन की पहली बैठक हुई। गठबंधन ने हमारे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के मकसद से उपचुनाव के लिए संयुक्त रूप से प्रचार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' की उम्मीदवार की जीत होगी।

अक्षय कुमार को थप्पड़ मारो, 10 लाख रुपये पाओ

नईदिल्ली। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है अक्षय कुमार को ओएमजी 2 में भगवान शिव का दूत के पोर्टल के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और नेटिज़न्स उनके चरित्र से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और इसे हिंदी देवताओं का अपमान बता रहे हैं। और सुपरस्टार के प्रति नफरत इतनी अधिक है कि कथित तौर पर हिंदू समूहों में से एक ने अभिनेता को किसी के द्वारा थप्पड़ मारने पर 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी है, और इससे पता चलता है कि हम कितने सहिष्णु हैं। आगरा में एक हिंदू संगठन ने भगवान शिव के दूत की भूमिका निभाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार को थप्पड़ मारने या थूकने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। उधर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने गुरुवार को अक्षय कुमार के पुतले और फिल्म के पोस्टर जलाए और कहा कि वे सिनेमाघरों के सामने प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अक्षय कुमार की ओएमजी 2 ने उन्हें अनावश्यक ध्यान और ड्रामा दिया है।

सोनीपत में हिंदू समूह ने हनुमान चालीसा का किया पाठ

नईदिल्ली। हरियाणा के सोनीपत में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने 31 जुलाई को नूंह जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में शनिवार को एक रैली आयोजित की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों का एक समूह कुंडली के पियाउ मनियारी इलाके में इकट्ठा हुआ और धार्मिक प्रार्थनाएं कीं खुला। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के कई हिस्सों में इसी तरह की सभाएँ देखी जा रही हैं। आयोजकों के अनुसार, उन्होंने नूंह में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर हमले के बाद 31 जुलाई को नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए हैं। हिंदू संगठन के एक नेता दीपक चौहान ने कहा कि देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मेवात में हुई हिंसा के विरोध में हमने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे बिना सत्यापन के किसी विशिष्ट समुदाय के सदस्यों और बाहरी लोगों को दुकानें नहीं देंगे।

गुजरातः तिरंगे के 'अपमान' वाला ऑडियो क्लिप वायरल

नईदिल्ली। गुजरात के पोरबंदर शहर में एक मौलवी को ऑडियो क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिरासत में ले लिया गया, जिसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर अपमान किया था। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) भागीरथ सिंह जडेजा ने कहा कि आरोपी की पहचान वासिद रजा के रूप में हुई है। रजा के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद कीर्तिमंदिर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जडेजा ने बताया कि मौलवी पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।एसपी ने कहा, ''पोरबंदर में नगीना मस्जिद के मौलवी से इस साल जनवरी में उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया था कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और उसे सलाम करना चाहिए तथा राष्ट्रगान गाना चाहिए।'' जडेजा ने कहा, ''एक ऑडियो प्रारूप में अपने जवाब में मौलवी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन उसे सलामी नहीं दे सकते। क्या मुसलमानों को राष्ट्रगान गाना चाहिए।

हर दिल जो जिहाद करेगा, पहचाना जाएगा,

धर्म छुपाकर शादी करने वाला 10 साल जेल की हवा खाएगा

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने तीन ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय कर सकते हैं। इन विधेयकों को पेश करते हुए शाह ने कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के पीएम मोदी सरकार के पांच प्रण के अनुरूप इन विधेयकों को लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगा। जिसमें धोखे से किसी महिला से शादी करने वालों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। पहचान छिपाकर शादी करने पर इस विशिष्ट प्रावधान को कुछ लोगों द्वारा गलत पहचान के तहत होने वाले अंतरधार्मिक विवाहों को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है। 11 अगस्त को लोकसभा में बीएनएस विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों से सख्ती से निपटते हैं।

धारा 69 शादी के झूठे बहाने या धोखेबाज तरीकों से यौन संबंध के बारे में क्या कहती है?

इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने के अलावा रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ पहली बार संबंध बनाना अपराध होगा।

शादी का वादा कर संबंध रेप की श्रेणी से अलग

शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के मामले को भी कानून में अलग से परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और वो वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है तो ऐसे मामलों को रेप की परिभाषा से अलग रखा गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है।

पहली बार इसे किया गया शामिल

ऐसा पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी। हालांकि, अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

लव जिहाद पर कैसे पड़ेगा असर

इस्लाम में जिहाद शब्द का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। वर्तमान हालात में लव जिहाद एक गढ़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। माना जाता है कि लव जिहाद वह धोखा है, जिसके तहत कोई मुस्लिम युवक या आदमी किसी गैर मुस्लिम युवती या महिला को प्रेम का जाल बिछाकर मुस्लिम बनने पर मजबूर करता है। लव जिहाद के ज़्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। अब इस बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर सजा मिलने का प्रावधान दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध पर लगाम लग सकेगी।

90 दिन में चार्जशीट, 30 दिन में फैसला

किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद एक महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा।

हथकड़ी का प्रयोग

एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वो आदतन अपराधी हो। इसके अलावा हिरासत से भागा हुआ या एक संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य में शामिल, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, हथियारों का अवैध कब्ज़ा, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध में शामिल रहा हो।

विशिष्ट सुरक्षा उपाय

सेक्शन 41, में किसी को अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिए जाने का प्रावधान है। यानी बिना सूचना दिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसमें सात साल से कम की सजा वाले मामले आते हैं। सीआरपीसी की धारा 41ए को एक नया नंबर धारा 35 मिलेगा।

दया याचिका

मौत की सजा पाए किसी दोषी की याचिका के निपटारे के बारे में सूचित किए जाने के बाद, वह या उसका कानूनी उत्तराधिकारी या रिश्तेदार 30 दिनों के भीतर राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। खारिज होने पर 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के पास दायर कर सकता है।

छत्तीसगढ़ में द केरला स्टोरी जैसी कहानी, छात्राओं को धर्मांतरण का सिखाया जा रहा पाठ

बिलासपुर। शहर के गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में द केरला स्टोरी के तर्ज पर कम्युनिटी विशेष के संदिग्ध गतिविधियों के संचालन का गंभीर मामला सामने आया है। इस्लामिक बैनर तले मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम पर क्लब और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसमें छात्र-छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। हैरान करने वाली बात ये है कि बकायदा इसमें विश्वविद्यालय के लोगो का भी इस्तेमाल किया गया है।

मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में गरमाया माहौल

बताया जा रहा है इसमें केरल की छात्राएं भी शामिल हैं। मामला उजागर होने के बाद यूनिवर्सिटी का माहौल गरमा गया है। अन्य छात्र और छात्र संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन सक्ते में है। कुलपति ने तत्काल मामले में जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है।

व्हाट्सएप ग्रुप से चलाते थे पूरा गेम

दरअसल, विश्वविद्यालय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से छात्र-छात्राओं को जुड़ने की अपील के बाद ये मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं से इसमें जुड़ने की

अपील की जा रही है। इसके लिए बकायदा इंस्टा सहित सोशल साइट पर इस्लामिक बैनर तले स्स्स्त्र ने अपना पेज भी बनाया है।

जिसमें बड़ी संख्या में केरल और अन्य राज्यों से आए छात्र-छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा जा रहा है। यही नहीं स्स्स्त्र को पॉलिटिकल पार्टी बताकर एक मलयाली फोरम भी बना दिया गया है। जिसमें सिर्फ मलयाली छात्र-छात्राओं को टारगेट किया गया है। हैरान करने वाली बात ये है कि बकायदा इसमें विश्वविद्यालय के लोगों का भी इस्तेमाल किया गया है। इधर कम्युनिटी विशेष का ग्रुप बनाकर इस तरह स्टूडेंट्स को जोड़ने के बाद विश्वविद्यालय में माहौल गरमा गया है।

अन्य छात्र और छात्र संगठन ऐसी गतिविधियों के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। छात्र संगठनों का सीधा आरोप है कि कुछ लोग और राजनीतिक पार्टियां जिनकी आईडियोलॉजी पाकिस्तान की है, वो लोग यहां एक्टिव हैं और विश्वविद्यालय के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं। हेल्प डेस्क बनाकर इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट के बच्चों को मेनुप्लेट करके ग्रुप से जोड़ा जा रहा है।

छात्र संगठनों ने मामले में प्रबंधन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ईधर मामले के उजागर होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन सक्ते में है। कुलपति सहित विश्वविद्यालय का प्रशासनिक हमला हरकत में आ गया है। आनन-फानन में तत्काल मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के लिए सभी डीन की एक कमेटी बनाई गई है, जो ग्रुप से जुड़े स्टूडेंट्स से पूछताछ कर रही हैं। कुलपति ने इसके साथ ही साफ किया है कि कोई भी ग्रुप या संगठन इस तरह विश्वविद्यालय के लोगों और अन्य अधिकृत दस्तावेज का उपयोग नहीं कर सकता है। कुलपति ने मामले में जांच के बाद प्रशासनिक और लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है।

हाईकोर्ट ने एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर लगाई रोक

■ सरकार को दिया दो सप्ताह का समय

बिलासपुर। बिलासपुर स्थित एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इसके बाद भी रजिस्ट्री होती है, तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा।

मामले में राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है कि इस रजिस्ट्री पर आपत्ति की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह का समय शासन को दिया है। कोर्ट ने नाराजगी भी जताई कि पिछले कई सालों से यह जमीन विवाद चल रहा है और अभी तक शासन की ओर कोई अपील या आपत्ति नहीं की गई। गौरतलब है कि बिलासपुर के जरहाभाठा स्थित एसबीआर कॉलेज के खेल मैदान के रूप में उपयोग हो रहे 2.38 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नीलामी के जरिए इस जमीन के बिक्री के आदेश दिए थे। साथ ही कहा गया था कि पूरी नीलामी प्रक्रिया कलेक्टर और रजिस्ट्रार की मौजदूगी में होगी। ट्रस्ट के एक पक्ष ने ऑक्शन नहीं करते हुए टेंडर किया और एक बड़े जमीन दलाल से इसकी बिक्री का सौदा कर लिया गया। साथ ही रजिस्ट्री कराने के लिए कागज पंजीयन ऑफिस में जमा करा दिए।

दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी मिली तो याचिकाकर्ता अतुल बजाज के माध्यम से उन्होंने रजिस्ट्री आफिस में आपत्ति की। साथ ही हाईकोर्ट की डीबी में अपील की। जब मामला सिंगल बेंच में चल रहा था तो शासन की ओर ना कोई वकील उपस्थित हुए और ना ही किसी अधिकारी ने जवाब दिया।

सीएम ने आदिवासी नेताओं के बोलने पर लगाया प्रतिबंध : अरविंद नेताम

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सर्व आदीवासी समाज समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद सर्व आदिवासी समाज के आयोजन में पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम शामिल होने पहुंचे। उन्होंने नई पार्टी बनाए जाने के सवालों पर कहा कि अब युवाओं को, नई पीढ़ी को जागरूक होना है और जल जंगल जमीन संसाधन जो खत्म हो रहे हैं उसके लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। जो आदिवासियों और मूल निवासियों के हित में बात करेगा उसी का शासन होगा। जब मीडिया ने पूछा कि कांग्रेस में वरिष्ठ मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज के हैं तो उन्होंने सीधे-सीधे आदिवासी कांग्रेस के नेताओं को सरकार के दलाल बताया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनको कुछ भी बोलने से मना किया है। मुख्यमंत्री भी समाज के नाम पर दलाली करने उतरे हुए हैं।

सर्व आदिवासी समाज के आयोजन में बालोद जिला सहित आसपास के आदिवासी एवं सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने अरविंद नेताम के समर्थन में कहा कि हमारे बुजुर्ग जो बोलेंगे वह हम करेंगे और जो भी मूल आदिवासियों मोर छत्तीसगढ़ के निवासियों के हित में बात करेगा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना उनके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। स्थानीय लोगों को उनका अधिकार दिलाना बेहद अनिवार्य है चाहे प्रशासन में हो चाहे उद्योग में हो, चाहे राजनीति में। हर तरफ हम मूल निवासियों को आगे देखना चाहते हैं। स्थानीय निवासी स्थानीय समाज को सर्वोच्च पदों पर देखना चाहते हैं हमारा समर्थन अरविंद नेताम जी के साथ हमेशा रहेगा।

सर्व आदिवासी समाज द्वारा इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी स्थानीय समाज के प्रमुखों को भी निमंत्रण दिया गया था। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बताया कि हम आप सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तभी हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ भला हो पाएगा और सब समाज मिलकर एक संगठन के रूप में आगे बढ़ेंगे तो हम हर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने में सफल हो पाएंगे बिखराव ही हम सबको पिछड़ा कर देता है।

विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहां पर हर वर्ग, हर समुदाय के लोग शामिल हुए तो आदिवासी समाज के युवक-युवतियों महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने सभी अतिथियों का पारंपरिक टीका चावल लगाकर अभिनंदन किया।

जगदलपुर में मतदाताओं को जागरुक करने का संकल्प, बीएलओ को दिलवाई गई शपथ

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग पूरे प्रदेश में मतदाता जनजागरुकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिला प्रशासन ने ऐसे इलाकों में चिन्हांकित किया है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कम मतदान हुआ था।ऐसे इलाकों में जाकर जिला प्रशासन की टीम लोगों को मतदान के लिए जागरुक कर रही है। कम मतदान वाले इलाकों में जागरूकता अभियान के तहत सभी को शपथ दिलाई जा रही है। ताकि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।

इसी कड़ी में बस्तर मुख्यालय जगदलपुर कलेक्टोरेट में जिला प्रशासन के सभी कर्मचारियों को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने शपथ दिलाई। शपथ में लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने की बात कही गई।

कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा 2 अगस्त से मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद लगातार चुनावी एक्टिविटी जारी रखी गई है। इसी क्रम में जगदलपुर विधानसभा के सभी क्षेत्र का ट्रेनिंग सेशन का कार्यक्रम रखा गया था। जिसमे जागरूकता अभियान के तहत शपथ दिलाई गई।

इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में जिन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है।वहां पर भी जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके।

मतदाता जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टोरेट परिसर में हुआ।जिसमें स्कूली बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार और एसपी दीपक झा ने किया। रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन,स्कूली बच्चे,सेक्टर अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रैली का समापन गार्डन चौक,बस स्टैंड होते हुए पंडित चक्रपाणि स्कूल मैदान में किया गया। जहां पर छत्तीसगढ़ के नक्शे को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शत-प्रतिशत मतदान कराने का संकल्प लोगों को दिलाया।

कवर्धा में मंत्री अकबर तो बेमेतरा में रविन्द्र चौबे करेंगे ध्वजारोहण

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आजादी के इस पर्व के मौके पर कबीरधाम और बेमेतरा जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों जिले में जिला स्तर पर समारोह आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर तो बेमेतरा में रविन्द्र चौबे ध्वजारोहण करेंगे।

प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वाजारोहण कर करेंगे। अकबर परेड की सलामी लेंगे और जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का देंगे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गरिमामय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सुबह नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का सम्मानित किया जाएगा। समारोह में पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य अतिथि प्रस्थान करेंगे। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राष्ट्रीय पर्व के आयोजन की तैयारियों के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए अलग-अलग दायित्व सौंपे हैं। वहीं, बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के विधायक व स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री रविंद्र चौबे जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे। जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान सुबह नौ बजे शुरू होगा। बेमेतरा डीएम पदुम सिंह एल्मा ने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर हड़ताल 15 से

कोरबा। कोरबा जिलान्तर्गत कटघोरा तहसील को पुन: जिला बनाने की मांग को लेकर युवाओं की टीम मैदान में उतर चुकी है। जिसमें जनप्रतिनिधि से लेकर समाजसेवी भी शामिल हैं। जिले की मांग को लेकर जनसेवक उत्तम सिंह रंधावा अन्य नगरवासियों के साथ 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इसका समर्थन सभी संगठनों ने किया है। इसकी वजह से अबकी बार क्षेत्रीय लोगों का मनोबल बढ़ा है और उम्मीद है कि जिला की उनकी मांग को सरकार जरूर मानेगी। क्षेत्रवासी लंबे समय से कटघोरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ता संघ इस मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल भी कर चुका है। इस मांग को लगातार उठाया जा रहा है। कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कटघोरा नगर को जिला बनाने की मांग लम्बे समय से चल रही है। इसी मांग को लेकर कटघोरा के उत्तम सिंह रंधावा, चंद्रकांत डिक्सेना, सुनील कुर्रे, रितेश गुप्ता, साकेत वर्मा, ठंडाराम उइके 230 किमी की रायपुर पदयात्रा भी कर चुके है। उसके बाद भी कटघोरा को जिला बनाने की मांग को पूरा नहीं किया गया है।

भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ने किया लाभार्थियों का सम्मान

कोरबा। भारतीय जनता पार्टी कोरबा मंडल ने नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 में पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी के मुख्य अतिथि में शक्ति केंद्र की बैठक और लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता निभाई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की उज्जवला गैस योजनाए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित कर विचारों का आदान-प्रदान और लाभार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 5 में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल मोदी ने अंग वस्त्र और श्रीफल से उन सब का सम्मान किया।इस मौके पर शक्ति केंद्र की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति केंद्र की गतिविधियों और बूथ स्तर पर किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

फेडरेशन की बैठक में लिये गए निर्णयों का कर्मचारियों को शीघ्र मिलेगा लाभ

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी एवं छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 01 की गत 26 जुलाई को संपन्न बैठक के जिन प्रमुख बिंदुओं पर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया था उसके आदेश शीघ्र जारी होंगे। उक्त जानकारी फेडरेशन के प्रांतीय प्रचार सचिव पवन दास ने देते हुए बताया कि फेडरेशन के महासचिव आर सी चेट्टी, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, जोनल सचिव राजेश खरे, चरित्र चौकसे, संतोष सिंह ठाकुर ने 8 अगस्त को तीनों ही कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों से कर्मचारियों से संबंधित 26 जुलाई की बैठक के चर्चा के बिंदुओं पर प्रगति की जानकारी ली। प्रबंधन की ओर से प्रतिनिधियों को बताया गया कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा अक्टूबर से लागू होगी। विभागीय एवं सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

बिना लाइसेंस उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की कार्यवाही

कोरबा। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक भण्डारण और बिक्री पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा पाली विकास खंड के ग्राम हरदी बाजार, सिरली, बोइदा, उतारदा, में कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें कान्हा कृषि केंद्र में पीओएस मशीन और भौतिक उपलब्ध खाद में भिन्नता पाए जाने पर नोटिस दिया गया एवं उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु वरिष्ठालय को पत्र प्रेषित किया गया। नारायण प्रसाद शर्मा ग्राम बोइदा में उर्वरक का भंडारण दर्शित नक्शे में ना करने पर एसएसपी का वितरण प्रतिबंधित किया गया नोटिस जारी किया गया। न्यू रमेश ट्रेडर्स में 8 बैग डीएपी बीमा पीओएस मशीन में एंट्री के पाया गया जिसे विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया पीओएस और उपलब्ध खाद की मात्रा में अंतर के लिए नोटिस जारी कर लाइसेंस निरस्त करने की प्रतिवेदन वरिष्ठलय को प्रेषित किया गया। इसी तरह यदुराज ट्रेडर्स हरदीबाजार में पीओएस मशीन और उपब्ध खाद की मात्रा का मिलान सही नही पाने पर प्रतिबंधित किया गया।

सड़क में दलदल, जिला प्रशासन को जगाने स्कूली बच्चों ने की धान की रोपाई

जशपुर। जिले में पंडरापाठ क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल हर्रापाठ में मुख्य सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों ने सड़क के कीचड़-पानी भरे गड्ढों में धान की रोपाई कर अनोखा विरोध-प्रदर्शन किया। दरअसल, हर्रापाठ से सोनक्यारी तक की 11 किलोमीटर सड़क कई सालों से अधूरी पड़ी है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को कीचड़ और पानी के गड्ढों से आने-जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क का निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का अनेक बार ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके उलट सड़क की बदहाली अब और बढ़ गई है। सड़क के गड्ढों में बच्चों और उनके अभिभावकों को धान का रोपा लगाते देख वाहन चालक भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिए थे।

सौर सुजला योजना से बलरामपुर के 9143 किसानों को मिला लाभ

बलरामपुर। सुदूर अंचल के किसानों को सौर सुजला योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान दो फसली लेकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सौर सुजला योजना बेहतर साबित हो रही हैं। सोलर पम्प प्रदाय कर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है, तथा यह लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास जल स्त्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं एवं बोरवेल पहले से ही उपलब्ध हैं। राज्य में इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में क्रेड़ा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले के 9143 किसानों को सौर सुजला योजना का लाभ दिया गया है। जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है।

अब किसानों को बरसात के पानी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। किसान अब योजना से लाभ लेकर दो से अधिक फसलों तथा साग-सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों की अच्छी फसल होने से उनके आय में वृद्धि हो रही है।

बलरामपुर जिले के विकासखण्ड रामचंद्रपुर के ग्राम चंदनपुर के किसान श्री बनारसी मेहता बताते हैं कि उनके पास 1.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिस पर उन्होंने नलकूप खनन के उपरांत क्रेडा विभाग के सहयोग से सिंचाई के लिए सोलर पम्प की स्थापना कराया है। वर्तमान में श्री मेहता द्वारा धान एवं साग-सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प की स्थापना के बाद दोहरी फसल का लाभ ले रहे हैं। जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम कृष्णानगर के किसान श्री सुकुमार द्वारा वर्ष 2023-24 में 03 एचपी क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना कराया गया। उनके पास लगभग 1.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वे बताते हैं कि इस साल वर्षा में विलम्ब होने के कारण धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन सोलर पम्प लगने से सही समय में धान की रोपाई का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि अब वे धान के अलावा साग-सब्जी का भी उत्पादन कर रहे हैं।

सौर सुजला योजना से आज जिले के किसान रबी एवं खरीफ फसलों के साथ-साथ साग-सब्जियों का उत्पादन बिना परेशानी के कर रहे हैं। सौर सुजला योजना से पानी की समस्या खत्म होने से सभी प्रकार के कृषि, सब्जी उत्पादन के साथ अन्य कार्य सुचारू तरीके से किया जा रहा है। किसान धान के साथ सब्जी की फसल भी ले रहे है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम कोटरकी के किसान श्रीमती आशामुनी ने बताया कि पहले खरीफ की फसल आसानी से हो जाती थी, लेकिन पानी की समस्या के कारण रबी की फसल लेने में दिक्कत होती थी। ऐन वक्त में बिजली की समस्या भी आ जाती थी, लेकिन अब सौलर पम्प लगने से बिजली-बिल की समस्या खत्म हो गई। अब वे खरीफ और रबी दोनों फसल बड़ी आसानी से ले पा रहे है और इससे उनकी आमदनी बढ़ी है।

देवगुड़ी और चारागाह में हुए भ्रष्टाचार पर गरमाई सियासत, भाजयुमो ने एफआईआर की मांग की

बीजापुर। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पामेड़ सेंचुरी क्षेत्र में देवगुड़ी निर्माण व चारागाह में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भाजयुमो मुखर हो गई हैं। भाजयुमो ने आदिवासियों की आस्था और क्षेत्र के विकास में बाधक बनने वाले अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की हैं।

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फूलचंद गागड़ा ने बयान जारी कर कहा है कि बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पामेड़ अभ्यारण्य क्षेत्र के कावरगट्टा में चारागाह व इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में देवगुड़ी बनाया जाना था। जिसमें भारी भ्रष्टाचार किये जाने की खबर समाचार पत्रों से मिली हैं। आरटीआई के माध्यम से मिले दस्तावेज और भौतिक सत्यापन से यह साफ हुआ है कि क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई चारागाह बना और न ही कोई देवगुड़ी बनी। लेकिन सम्बंधित रेंज के अफसरों ने कार्य पूर्ण बताकर पूरी राशि आहरण कर लिया।

फूलचंद गागड़ा ने बयान में बताया है कि चारागाह के लिए 3 लाख 31 हजार 284 रुपये और देवगुड़ी के नाम पर 10 लाख रुपये का आहरण विधिवत तरीके से किया गया हैं। उन्होंने बताया कि इस खेल के लिए बाकायदा फर्जी मस्टररोल फर्जी मजदूरों की एंट्री व ऑफिस में बैठकर अफसरों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। गागड़ा ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से आदिवासियों की आस्था देवगुड़ी और जिले की विकास में बाधक बन रहे अफसरों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली सेवा अधिनियम बन गया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम कानून बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश को बदलने के लिए है। इसके बाद इसे 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर केंद्र सरकार को अधिकार देने वाला विधेयक उच्च सदन में में भी पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 131 वोट आए थे जबकि 102 वोटों इसके खिलाफ थे। विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। सरकार द्वारा दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए संसद में एक विधेयक पेश किए जाने के बाद संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा, अधिकांश विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ थे।

वॉकआउट ने विपक्ष की योजना और इरादे को उजागर किया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान लोकसभा से वॉकआउट करने पर शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उनके वॉकआउट से उनकी योजना का पता चलता है कि उनका मणिपुर से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सिर्फ संसद को बाधित करना चाहता है। सीएम सरमा ने कहा, विपक्ष ने मांग की कि पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलना चाहिए और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे बाहर चले गए। इससे उनकी योजना पूरी तरह से उजागर हो गई कि विपक्ष का इरादा मणिपुर से कोई लेना-देना नहीं था। वे सिर्फ संसद को बाधित करना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के भाषण की भी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने दिल से बात की और उन्होंने मणिपुर के लोगों के प्रति अपना स्नेह दिखाया। सीएम सरमा ने कहा, पीएम मोदी ने अपने दिल से बात की। उन्होंने मणिपुर के लोगों के प्रति अपना स्नेह भी दिखाया।

राहुल गांधी 7 सितंबर से जाएंगे यूरोप की यात्रा पर

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 से 11 सितंबर तक यूरोप की यात्रा पर जाएंगे जहां वह प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी फ्रांस के पेरिस जाएंगे जहां वह भारतीय प्रवासियों से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता नॉर्वे और बेल्जियम का भी दौरा करेंगे जहां वह ब्रूसेल्स में यूरोपीय संघ संसद का दौरा करेंगे। वह यूरोपीय संघ के सांसदों से मुलाकात करेंगे। उनके बेल्जियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने की संभावना है। सात अगस्त को लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की यह पहली विदेश यात्रा है। दिलचस्प बात यह भी है कि जब जी20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे उसी दौरान राहुल की यह यात्रा होगी। राहुल इससे पहले इस साल मई में 10 दिवसीय संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों, सांसदों और अन्य लोगों के साथ बातचीत की थी।

स्मृति ईरानी के बयान पर रॉबर्ड वाड्रा का पलटवार

नईदिल्ली। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए वाड्रा ने कहा कि भारत उनके रेस्तरां और डिग्रियों के बारे में जानना चाहता है। वाड्रा ने मंत्री से कहा कि वह उनके नाम के प्रति मुग्ध होना और संसद में उनके नाम का दुरुपयोग करना बंद करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्मृति ईरानी, मेरे प्रति आसक्त होना और संसद में मेरे नाम का दुरुपयोग करना बंद करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप सबूत दें या फर्जी होना बंद करें, जैसे कि आप हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आपकी अक्षमताएं मुझ पर उंगली उठाकर छिप नहीं सकतीं, याद रखें जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बाकी उंगलियां आपकी ओर उठती हैं, इससे जुड़े कई और विवाद हैं आपको और आपके परिवार को लेकर। वाड्रा ने आगे कहा, भारत गोवा में आपके रेस्तरां और देश के विभिन्न हिस्सों में तीसरे पक्ष के नामों के बारे में जानना चाहता है? आपकी डिग्री/शैक्षिक योग्यता और इसके साथ अंतर्निहित विवाद! पहले आप इसे स्पष्ट करें और फिर दूसरों पर उंगली उठाएं।

उपेंद्र कुशवाहा ने राजद प्रमुख लालू यादव पर कसा तंज

पटना। राष्ट्रीय लोक जनता दल(रालोजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव खुद तो मुखिया का चुनाव तक नहीं लड़ सकते और वो दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते हुए फिर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि जिनका खुद चुनाव लड़ने का लाइसेंस छीन लिया गया हो, वह दूसरे को प्रमाण पत्र नहीं बंटा करते है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि लालू यह बात शायद भूल गए हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित किया है। लोकतंत्र की प्रकिया में अब वो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। जिनका खुद का नेता होने का लाइसेंस छीन लिया गया है, वो क्या दूसरे को नेता होने का प्रमाणपत्र बांटेंगे! बता दें कि इससे पहले पटना में लालू यादव से पत्रकारों ने यह सवाल किया था कि कुशवाहा लगातार नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो लालू ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कोई नेता है क्या?

प्रधानमंत्री ने हावड़ा में भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया

विपक्ष के लोग सदन से भागे, पूरे देश ने देखा मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात : मोदी

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। अगर वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन बेनकाब हो जाता। विपक्ष के लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया।

मणिपुर को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा था। वे बिना किसी तर्क के बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहता है और इसलिए वे लोकसभा में बिना किसी तर्क के बोल रहे हैं।

उन्होंने कहा हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सदस्य बिना अहंकार के काम करते हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा, जो लोग खुद को लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में चित्रित करते हैं, वे ही ईवीएम से छुटकारा पाने की साजिश रचते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों और वंचितों पर सबसे अधिक पड़ता है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन और बाजार को प्रभावित करता है तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 'जी-20 भ्रष्टाचार निरोधक मंत्रिस्तरीय बैठक' को डिजिटल माध्यम से

संबोधित करते हुए कहा, ''भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सख्त नीति है।' उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था क्योंकि यह सच का एहसास नहीं होने देता।

मोदी ने कहा, ''हम आर्थिक अपराधियों का आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे हैं। हमने आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया है और आर्थिक अपराधियों एवं भगोड़ों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की पूंजी बरामद की है।'' उन्होंने कहा कि जी-20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैंने 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन में पूंजी वसूल करने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में नौ सूत्री एजेंडा पेश किया था। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आपका समूह निर्णायक कदम उठा रहा है।''

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लेखा परीक्षा संस्थानों को सम्मान दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में खामियों को दूर किया गया है और प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए लाभार्थियों को 360 अरब डॉलर दिए गए हैं।

पीएम मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी

सागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक स्थल पर भूमि पूजन किया। सागर के बड़तूमा पहुंचकर 14वीं सदी के कवि एवं समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री का करीब एक महीने में प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले एक जुलाई को मोदी ने शहडोल जिले के पकरिया गांव में आदिवासी नेताओं, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी। कार्यक्रम में सत्तारूढ़ पार्टी की चल रही समरसता (सद्भाव) यात्रा का समापन भी होगा। प्रधानमंत्री के इन दोनों कार्यक्रमों को चुनाव से पहले दलितों तक पहुंचने के पार्टी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पांच समरसता यात्राएं 25 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न हिस्से से शुरू हुई है। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीट में से 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और भाजपा ने इनमें से पिछले चुनाव में 18 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीट मिली थीं। कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सतना जिले के पवित्र शहर मैहर में 3.5 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण कराया है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक, संत रविदास के दलित अनुयायी राज्य में अनुसूचित जाति आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं।

कांग्रेस नेता बोले- पीएम हर मुद्दे पर बोलते हैं, मणिपुर पर चुप क्यों?

हमें मजबूर होकर लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव : अधीर रंजन

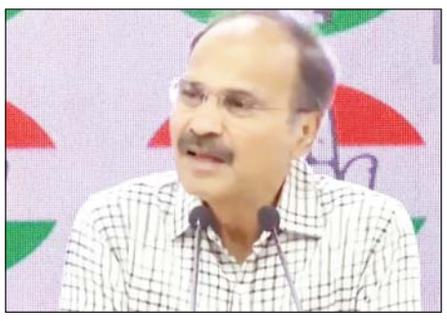

नईदिल्ली। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक चर्चा हुई। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। हालांकि, इस को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हमने मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले पर बोले। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम मसलों पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर इतने चुप क्यों हैं?

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की थी। हम चाहते थे कि संसद चले। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का अंतिम उपाय करना पड़ा कि प्रधानमंत्री संसद में बोलें। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास पर बहस लंबित थी तब वे(भाजपा) संसद में विधेयक पारित कर रहे थे। विपक्ष को कई विधेयकों पर अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मोदी जी इंडिया शब्द के विरोध में क्यों हैं?...इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक नई घटना है जिसे हमने संसद में अपने करियर में पहले कभी अनुभव नहीं किया है। यह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा एक जानबूझकर की गई योजना है। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर देगा।

निलंबन पर बोले चौधरी, जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित किए जाने और संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई कार्यवाही को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधीर रंजन चौधरी और पवन खेड़ा ने संबोधित किया।

लोकसभा से अपने निलंबन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। उन्होंने आगे कहा, साल 1978 में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसी दिन प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो गई थी। नतीजा ये निकला कि सदन सुचारू रूप से चला। जब प्रधानमंत्री मोदी, चांद से लेकर चीता तक पर बात करते हैं तो विपक्ष को लगा कि वे मणिपुर पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधीर रंजन ने अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद संसद में कई बिल पारित कराने को गलत बताते हुए कहा, जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म न हो, तब तक किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह हमारे सदन की परंपरा है। लेकिन मोदी सरकार ने सभी परंपरागत तौर-तरीकों की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित कर दिए। इस दौरान विपक्ष को किसी भी विधेयक पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया। मणिपुर में हालात को अब भी बेहद चिंताजनक बताते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि मणिपुर में मैंने बफर जोन में सुरक्षा बलों को तैनात किया है, यानी सदन में वे खुद स्वीकारते हैं कि मणिपुर के हालात बेहद बिगड़ चुके हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया कप : बांग्लादेश ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की

ढाका। बांग्लादेश ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। अनकैप्ड ओपनर तंजिद हसन को शामिल किया है। युवा बल्लेबाज शमीम पटोवारी पहली बार टीम में दिखेंगे। टी20ई में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, को वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया।

मेहदी हसन मिराज की भी वापसी हुई, जिन्होंने आखिरी बार 2021 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। हसन इमर्जिंग एशिया कप में अपने प्रदर्शन के दम पर आए हैं, जहां उन्होंने तीन अर्धशतक बनाए। तमीम इकबाल को शामिल नहीं किया गया। तमीम पीठ की चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गये है जिससे टीम का पारी की शुरुआत करने वाला एक स्थान खाली हो गया।

बीसीबी मुख्य चयनकर्ता मिन्हाजुल अबेदीन ने कहा, 'तंजिद पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हाल में एमर्जिंग एशिया कप में उसने शानदार खेल दिखाया।' मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के बाद टीम से बाहर किये गये अनुभवी महमूदुल्लाह की फिटनेस शिविर में बुलाये जाने के बावजूद अनदेखी की गयी।

एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया है जो 31 अगस्त को पहला मैच सह मेजबान श्रीलंका के खिलाफ कैंडी में खेलेगा। दूसरे मैच में तीन सितंबर को बांग्लादेश की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी।

पूरी टीम- शाकिब अल हसन (कप्तान), लिट्टन दास, तंजिद हसन, नजमुल हुसैन शांटो, तौहिद हृदोय, मुश्फिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, शेख मेहदी, नासुम अहमद, शमीम हुसैन, नईम शेख। स्टैंडबाय- ताइजुल इस्लाम, सैफ हसन, तंजिम हसन साकिब।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

नेपाल भारत को टमाटर एक्सपोर्ट करने को तैयार

नईदिल्ली। नेपाल दीर्घकालिक आधार पर भारत को बड़ी मात्रा में टमाटर निर्यात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने इसके लिए बाजार तक आसान पहुंच और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग की है। भारत में टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए इस तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है। पड़ोसी देश का यह आश्वासन उस समय आया, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में बताया कि भारत ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण भारत में टमाटर की खुदरा कीमतें लगभग 242 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और देश पहली बार टमाटर का आयात कर रहा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि उनका देश दीर्घकालिक आधार पर भारत को टमाटर जैसी सब्जियां निर्यात करने का इच्छुक है, लेकिन इसके लिए भारत को अपने बाजार तक आसान पहुंच देनी होंगी।

ओएनजीसी की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 34 प्रतिशत घटा

नईदिल्ली। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 34 प्रतिशत गिर गया। तेल की कीमतों में गिरावट और कम उत्पादन के कारण शुद्ध लाभ में कमी हुई। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 10,015 करोड़ रुपये रह गया, जबकि बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 15,206 करोड़ रुपये था। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भारत की सबसे बड़ी उत्पादक ओएनजीसी ने पिछले साल कच्चे तेल पर प्रति बैरल 76.49 डॉलर कमाए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 108.55 डॉलर प्रति बैरल था। तेल की कीमतें जून, 2022 तिमाही में दुनियाभर में तेजी से बढ़ी थीं, जब रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद आपूर्ति एवं मांग में अनिश्चितता आ गई थी।

एनबीसीसी का नेट प्रॉफिट 77.41 करोड़ रुपये पर पहुंचा

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 77.41 करोड़ रुपये का हुआ। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कंपनी को बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,965.80 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,853.24 करोड़ रुपये थी। एनबीसीसी परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और रियल एस्टेट कारोबार में है। एनबीसीसी ने बयान में कहा कि कंपनी का 94.6 प्रतिशत राजस्व पीएमसी खंड और पुनर्विकास कार्यों से आता है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घर, कार लोन रेट में 0.20 फीसदी तक कटौती की

नईदिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शनिवार को गृह और कार ऋण पर ब्याज दर में 0.20 फीसदी तक की कटौती की। इसके अलावा बैंक ने प्रसंस्करण शुल्क को मान करने की घोषणा भी की। इस कटौती के साथ गृह ऋण अब मौजूदा 8.60 प्रतिशत की जगह 8.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होगा। दूसरी ओर कार ऋण को 0.20 प्रतिशत सस्ता कर 8.70 प्रतिशत कर दिया गया है। बीओएम ने एक बयान में कहा कि नयी दरें 14 अगस्त से प्रभावी हैं। बैंक ने कहा कि कम ब्याज दरों और प्रसंस्करण शुल्क में छूट के दोहरे लाभ से ग्राहकों को वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

भुगतान प्रणाली का गेमचेंजर बनेगा यूपीआइ

डॉ अश्विनी महाजन

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में भारत के भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआइ को शुरू किया गया। देखने में भले यह एक छोटी शुरुआत लगती हो, यह भारत के भुगतान प्रणाली की दुनिया में बढ़ती पहचान का द्योतक है। यूपीआई की शुरुआत 2016 में भारत सरकार द्वारा समर्थित एजेंसी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) द्वारा की गयी थी।

यह एक त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के बीच धन का स्थानांतरण किया जाता है। यह भारतीय रुपये पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में यूपीआइ के इस्तेमाल के लिए यूपीआइ इंटरनेशनल का एक नया फीचर यूपीआइ में शामिल किया गया है। जिससे क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेशों में भुगतान किया जा सकता है।

भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2014 में रुपे कार्ड का चलन शुरू हुआ था। बाद में ऑनलाइन भुगतानों में सुविधा के लिए यूपीआई शुरू किया गया। आज भारत में अनेक प्लेटफॉर्म हैं जो यूपीआइ से जुड़कर अपने ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। ऑनलाइन, यानी डिजिटल भुगतान का चलन पूरी दुनिया में बढ़ा है, लेकिन यह सबसे अधिक भारत में बढ़ा है। वर्ष 2022 में कुल 149.5 लाख करोड़ रुपये के ऑनलाइन लेनदेन हुए। इनमें 126 लाख करोड़ के लेनदेन केवल यूपीआइ के माध्यम से हुए। देश में लगभग 88 अरब ऑनलाइन लेनदेन रिकॉर्ड किये गये। प्राइसवाटरहाउस कूपर की रिपोर्ट की मानें,

तो ऑनलाइन भुगतान की संख्या 2026-27 तक एक अरब प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। दुनिया में जितने ऑनलाइन लेनदेन होते है, उसके 40 प्रतिशत से ज्यादा भारत में होते हैं।

भारत में ऑनलाइन लेनदेन पूर्णतया निःशुल्क रहा है। हाल ही में सरकार ने 2000 और उससे ऊपर की राशि पर उपभोक्ता द्वारा मर्चेंट को खरीदारी के लिए भुगतान पर 1.1 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने की अनुमति दी है। परंतु यदि उपभोक्ता द्वारा मर्चेंट के बैंक अकाउंट में भुगतान किया जाता है, तो यह शुल्क लागू नहीं होगा।

यूपीआइ के लिए अंतरराष्ट्रीय एनपीसीआइ एक प्रमुख प्राथमिकता है। वर्ष 2022 में, एनपीसीआइ ने घोषणा की कि वह यूपीआइ भुगतान को सक्षम करने के लिए कई देशों में बैंकों और भुगतान कंपनियों के साथ काम करेगी। तब से यूपीआइ को कई देशों में लॉन्च किया जा चुका है और कई अन्य देशों में इसके लिए तैयारी चल रही है। यूपीआइ के अंतरराष्ट्रीयकरण से उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को कई लाभ मिलेंगे। उपयोगकर्ताओं के लिए इसका मतलब होगा कि वे अपने स्थान के अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर भी अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यापारी व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और भारतीय ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होंगे। यूपीआइ का अंतरराष्ट्रीयकरण इस बात का प्रमाण है कि यूपीआइ भारत में सफलता का परचम लहराने के बाद वैश्विक भुगतान परिदृश्य को बाधित करने की क्षमता रखती है। यह सुविधाजनक होने के साथ-साथ सुरक्षित भुगतान प्रणाली भी है, जो उपयोगकर्ताओं के खातों की सुरक्षा के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। इसलिए लेनदेन के इतने बड़े प्रमाण के बाद भी धोखाधड़ी न्यूनतम है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में लागत बहुत अधिक है। यूपीआइ के अंतरराष्ट्रीयकरण से सीमा पार भुगतान की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। बीते वर्ष रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय प्रणाली 'स्विफ्ट' में अचानक आयी रुकावट के बाद यूपीआइ को वैश्विक बनाने की मुहिम तेज हो गयी है। चूंकि यूपीआइ भारतीय रुपये पर आधारित है, इसलिए इसके अंतरराष्ट्रीयकरण से अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसानी से भारतीय रुपये में हो सकेगा।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल पर विवाद

विजय विद्रोही

चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है। ऐसे ही, सरकार का काम अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त चुनना नहीं है। पर यह सवाल नए विधेयक के साथ खड़ा हो गया है, जिसमें सरकार ने चुनाव आयुक्त के चयन का नया आधार तय किया है। नया विधेयक अगर कानून का रूप ले लेता है, तो चुनाव आयुक्तों का चुनाव प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत उनके ही मंत्रिमंडल के कोई एक वरिष्ठ मंत्री करेंगे। साफ है कि दो का झुकाव एक तरफ होने की संभावना या आशंका बनी रहेगी, लिहाजा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ बैठकर चुनाव आयुक्त का नाम तय कर लेते थे। ऐसे में चुनाव आयुक्त कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, उस पर ठप्पा लग जाता था। इस व्यवस्था की आलोचना होती रही, पर बदलाव नहीं हुआ। इस बीच सीबीआई निदेशक, मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त सभी की नियुक्ति एक समिति करती रही, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को स्थान दिया गया। पर चुनाव आयुक्त के मामले में सरकार छूट लेती रही, जिस पर विवाद भी होते रहे और अदालत में वाद भी। ऐसा ही एक वाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें पंजाब कैडर के एक आईएएस अधिकारी को रिटायरमेंट के छह घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जब तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर नया बिल नहीं लाती, तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। पर नए बिल में प्रमुख न्यायाधीश की भूमिका समाप्त कर दी गई है। तर्क दिया जा रहा है कि प्रमुख न्यायाधीश कानून के ज्ञाता हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि उन्हें सचिव स्तर के सरकारी अधिकारियों के कामकाज की भी जानकारी हो। एक तर्क यह भी दिया गया कि चूंकि चुनाव आयुक्त का मसला कोर्ट में गया है, लिहाजा प्रमुख न्यायाधीश का नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा होना उचित नहीं। पर सीबीआई निदेशक का चयन भी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ सीजेआई करते हैं और सीबीआई के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी करता है, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई पर नैतिक हदबंदी क्यों मानी जाए? विधेयक में व्यवस्था की गई है कि अब सचिव स्तर के नीचे के अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं होगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सिलेक्ट कमेटी बनेगी, जो पांच नामों की सिलेक्शन कमेटी बनाएगी और उन पर कमेटी विचार करेगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इसका स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि पहले किसी को भी चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन बिल कहता है कि कमेटी चाहे, तो भेजे गए नामों के अलावा किसी अन्य को भी चुनाव आयुक्त बना सकती है। जानकारों का कहना है कि यह तो हस्तक्षेप की गली है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक, बिल में यह प्रावधान होना चाहिए कि कमेटी सर्वसम्मति से एक नाम पर एकमत हो। वह कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों का चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से यकीन उठता जा रहा है। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 40 फीसदी वोटरों ने चुनाव प्रक्रिया पर शक जताया था। चुनाव आयोग चुनावों को कैसे प्रभावित कर सकता है? एक, सत्ता की सुविधानुसार चुनाव की तारीखों व चरणों का एलान कर। लंबा चुनाव पैसेवाली पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि छोटे दल तो दूसरे चरण के बाद ही हांफने लगते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव में कौन पास, कौन फेल

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति के हर कदम के कुछ घोषित, तो कुछ अघोषित मकसद होते हैं। यह भी दिलचस्प है कि उसके घोषित मकसद से कहीं ज्यादा अघोषित और सांकेतिक मकसद महत्वपूर्ण होते हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव का घोषित मकसद मणिपुर के मामले को राष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा बनाना रहा, लेकिन इसका अघोषित मकसद आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा तय करना और उसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना था। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी बहिर्गमन के बाद ध्वनि मत से गिर चुका है और आगामी लोकसभा चुनाव तक के लिए मोदी सरकार की राह का कांटा दूर हो गया है। इसके बाद यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव अपने घोषित और अघोषित दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहा?

इसमें दो राय नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव अपने घोषित मकसद में किंचित कामयाब रहा, लेकिन वह अपने सांकेतिक और अघोषित लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, एक तरह से कांग्रेस ने तश्तरी में सजाकर मोदी सरकार को अगले चुनाव के लिए अपना एजेंडा स्थापित करने और उसी के अनुरूप चुनाव अभियान चलाने की सहूलियत प्रदान कर दी है। सबसे पहली बात यह कि जिस कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, उसके प्रदर्शन को देखना होगा। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना, पहला संबोधन था। उनके चाहने वाले ही नहीं, विरोधियों की भी निगाह राहुल गांधी के संबोधन पर थी। चाहने वाले इस उम्मीद में थे कि अपने भाषण के जरिए वे केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत घेरेबंदी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आशंकित था कि राहुल कहीं नया टंटा न खड़ा करें। लेकिन राहुल ने अपने अनुयायियों को जहां निराश किया, वहीं सत्ता पक्ष को राहत दे दी। उनके लचर प्रदर्शन के बाद अब सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में बार-बार उन्हें अयोग्य बताएगा, उनकी नाकामियां गिनाएगा। सत्ता पक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि राहुल भले ही अधेड़ हो चुके हों, लेकिन उनमें अभी भी बचपना है। सत्ता पक्ष वोटरों को यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि देश किसी अपरिपक्व के हाथ में नहीं दिया जा सकता।

कांग्रेस और उसके रणनीतिकार भूल गए कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने यह समूचे देश को संबोधित करने का मौका है। एक शानदार अवसर वे चूक गए। वाममोर्चे के एक-दो सदस्यों को छोड़ दें तो समूचा विपक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव पर दिशाहीन नजर आया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से भी उम्मीद थी कि वे कुछ तर्क देंगी। लेकिन उन्होंने भी निराश किया। एक दौर में समाजवादी राजनीति अपनी धारदार भाषण कला और तर्कों के कारण जानी जाती थी। लेकिन चाहे जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल, उसके सदस्य भी कोई धारदार और वजनी तर्क पेश नहीं कर पाए। जनता दल यू के सांसद गिरधारी यादव के संबोधन का आशय क्या रहा, वह शायद ही लोकसभा के सदस्य कुछ समझ पाए होंगे। विपक्ष के तर्कों के बरक्स भाजपा की दलीलें देखिए। भाजपा की ओर से चर्चा की शुरूआत करते हुए निशिकांत दुबे ने तर्क, तथ्य और तंज तीनों का अद्भुत मेल दिखाया। उनके तंज गहरे चुभन वाले रहे, लेकिन भाषा और तर्क ऐसा रहा कि जिस कांग्रेस पर वे हमला कर रहे थे, उसके सदस्य भी मंद स्मित से भरे नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह की ख्याति बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर नहीं रही है। लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन की चर्चा में जिस तरह तर्क, तंज और तथ्यों का मेल दिखाया, वह अद्भुत रहा। उन्होंने विपक्षी आरोपों के खिलाफ दमदार तर्क रखे, अपनी सरकार की उपलब्धियां रखीं और लगे हाथों टोकाटाकी करते रहे सदन में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को अपनी पार्टी के हिस्से से बोलने के लिए वक्त देने का ऐलान कर दिया। सवाल उठाने वाले सांसदों मसलन दानिश अली आदि को सीधे संबोधित करते हुए उनके आरोपों की धज्जी उड़ा दी। यह सब जानते हैं कि मणिपुर हिंसा के लिए मैती समुदाय से कहीं ज्यादा जिम्मेदार कुकी समुदाय है। लेकिन संसदीय व्यवहार के अनुरूप उन्होंने जब भी कुकी समुदाय का जिक्र किया, हर बार उन्हें कुकी भाई कहा। कह सकते हैं कि अमित शाह का यह भाषण राजनेता से स्टेट्समैन की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक रहा। उनकी जैसी अक्खड़ छवि रही है, उनके भाषण में किंचित वह रही, लेकिन ज्यादातर वक्त वे विनम्र दिखते रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो राहुल गांधी एक वरदान समान हैं। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, अलबत्ता इस तथ्य को स्वीकार भी किया। अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव, चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री को ही देना होता है। इस नाते उनकी बारी सबसे आखिर में आती है। चूंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, इसलिए वह प्रधानमंत्री के जवाब के बाद स्पष्टीकरण मांग सकती थी। लेकिन उसने खुद ही यह मौका खो दिया। वह ठोस और जानदार आरोप नहीं लगा सकी और आखिर में स्पष्टीकरण के वक्त समूचे विपक्ष के साथ सदन से बहिर्गमन कर गई। प्रधानमंत्री को एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव ने मौका दे दिया। उनके जवाब को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहले हिस्से में उन्होंने जहां अपने नौ साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की गिनती कराई, वहीं मणिपुर समेत समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं के लिए अतीत की कांग्रेस सरकारों के कदमों को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने लोहिया को उद्धृत करते हुए पूर्वोत्तर की अशांति के लिए नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

वेरियर एल्विन के सुझाव पर नेहरू ने पूर्वोत्तर को एक तरह से संरक्षित और बफर जोन बना दिया था, जहां विकास की किरणें नहीं पहुंचनी थी। नेहरू शासन में पहुंची भी नहीं। इसका लोहिया ने विरोध करते हुए कहा था कि तीस हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कोल्डस्टोरेज में तब्दील करके उसे विकास से वंचित कर दिया गया है। लोहिया ने उस क्षेत्र में घुसने का बार-बार प्रयास किया और संरक्षित क्षेत्र बनाने का बार-बार विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लोहिया के बहाने कांग्रेस के साथ खड़े समाजवादी दलों को भी निशाना बनाया। मणिपुर की समस्या के लिए उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर रहस्यपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालतों में जो हो रहा है, वह सबको पता है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि अधीर रंजन चौधरी भले ही इस बात पर खुश होते रहें कि विपक्ष ने पीएम को संसद में बोलने के लिए विवश कर दिया लेकिन यह बोलना क्या विपक्ष के हित में गया है? इस मौके का उपयोग उन्होंने देश को संबोधित करने के रूप में लिया और इसका भरपूर फायदा उठाया। एक तरह से मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरूआत कर दी, जिसका कम से कम विपक्ष को तो कोई फायदा नहीं होने वाला।

कृपया इनसे सीखें

कुशीनगर में तो भोजन वाली अम्मा हैं

गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। हमारे समाज में बहुतों ने इसे आत्मसात किया और इसे अपने जीवन का आधार बना लिया। ऐसी ही एक शख्सियत हैं। भोजन वाली अम्मा। उम्र लगभग 60 वर्ष, नाम रेखा देवी, माली हालत भी ठीक नहीं लेकिन जज्बा ऐसा कि पहचान बन गई भोजन वाली अम्मा के रूप में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित पड़रौना में साल भर वह प्रत्येक शनिवार को गरीबों, कुष्ट रोगियों व दिव्यांगों को भोजन कराती हैं। खास बात यह कि वह

पूरी व्यवस्था बिना किसी सरकारी मदद के करती हैं। उनकी लगन को देखते हुए अब (पिछले दो वर्ष से) कुछ लोग सहयोग को आगे आने लगे हैं। लगभग 18 वर्ष पूर्व शुरू किया गया यह सेवा कार्य आज भी अनवरत जारी है। जो पहुँच गया, उसे खाना मिलना ही है। सैकड़ों की संख्या का क्रम सुबह दस बजे से दो बजे तक और फिर शाम को छह बजे से आठ बजे तक जारी रहता है। कोलकाता निवासी रेखा देवी बताती हैं कि पड़रौना नगर के तिलक नगर निवासी रघुनाथ उर्फ सुग्गा बाबा के साथ उनकी शादी हुई थी। एक दिन पति के साथ बाजार निकली थी तो देखा कि भूख से परेशान एक गरीब व्यक्ति मिट की दुकान पर गिड़गिड़ा रहा था। परेशान गरीब के चेहरे की उदासी और पीड़ा उनके मन को छू गयी। लौटकर घर आई दुकान का दृश्य उन्हें बार-बार परेशान करने लगा, फिर क्या उन्होंने संकल्प लिया कि अपनी क्षमता के अनुसार, गरीबों को भोजन कराएँगी और उनकी सेवा करेंगी।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2004 ग्रीस के एथेंस में 28 वां ओलंपिक खेलों की शुरूआत हुई।

2006 टोक्यो में एक अनजाने ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा जो इस दिन कुछ घंटे लंबा था। बिजली की विफलता सुबह की भीड़ के घंटे में हुई और व्यापार के सामान्य प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि श्रमिकों को देरी हुई और कंपनियां अपना दिन शुरू नहीं कर सकीं।

2007 पुरातत्वविदों ने रडार इमेजरी का उपयोग करते हुए बताया कि खमेर साम्राज्य की पूर्व राजधानी अंगकोर, 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाला और 5000000 की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रीइंडस्ट्रियल शहरी केंद्र था।

2010 कनाडाई अधिकारियों द्वारा बोर्ड किए जाने के बाद, एमवी सनसिया ने डॉक किया और 492 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी दावेदारों को हिरासत में ले लिया गया।

2011 स्कॉटलैंड के एबरडीन से शेल 113 मील की दूरी पर गनेट अल्फा प्लेटफॉर्म के पास एक टूटी हुई तेल पाइपलाइन पाई जाती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

नारायणोपनिषद (भाग-2)

गतांक से आगे...

यह एक अक्षर है। नम: ये दो अक्षर हैं और नारायणाय ये पाँच अक्षर हैं। इस प्रकार यह नमो नारायणाय पद भगवान् नारायण के आठ अक्षरों से युक्त मन्त्र है। भगवान् नारायण के इस अष्टाक्षरी मन्त्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है, वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पूर्णायुष्य प्राप्त करता है। उसे जीवों का आधिपत्य, स्त्री- पुत्र एवं धन-धान्यादि की वृद्धि तथा गौ आदि पशुओं का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। तदुपरान्त वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, यही सामवेदीय उपनिषद् का प्रतिपादन है।

अ कार, उ कार और म कार मात्राओं से युक्त यह प्रत्यक् (कार) आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवस्वरूप है। ये भिन्न-भिन्न हैं, इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को कहते हैं। इस प्रणवरूप कार का जप करके योगी-साधक जन्म-मृत्यु रूपी सांसारिक बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नमो नारायणाय इस मन्त्र की साधना करने वाला साधक वैकुण्ठ धाम को जाता है। वह यह वैकुण्ठ धाम पुण्डरीक (हृदय कमल) विज्ञानमय है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत् के सदृश परम प्रकाशस्वरूप है। ब्रह्ममय देवकी नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात् ब्राह्मण प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुण्डरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत हैं। प्राणिमात्र में वे भगवान् नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित हैं। वे ही परब्रह्म हैं। विद्वज्जन अथर्ववेदीय कार रूपी इस शिरोभाग (सारभाग) का अध्ययन करते हैं।

इस उपनिषद् का प्रात: काल पाठ करने से रात्रि में किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रात: एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद् का पाठ करने से साधक पूर्व समय (पूर्वजन्म) का भी यदि पापी हो, तो वह पापरहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान् भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य पाँच महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है।

वह चारों वेदों के पाठ का पुण्यलाभ प्राप्त करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अन्तकाल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है, वह भी श्रीमन्नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है।

सुशासन का पर्याय थीं धर्मपरायण राजमाता अहिल्यादेवी होलकर

प्रहलाद सबनानी

भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए अपनी राज्य सत्ता को सफलतापूर्वक चलाने के सिलसिले में भारत का इतिहास यूं तो कई सफल नेत्रियों एवं महारानियों से भरा पड़ा है, परंतु यह इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसी कड़ी में मालवा राज्य की राजमाता अहिल्यादेवी होलकर का नाम भी बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। आपने मालवा राज्य पर 28 वर्षों (1767 से 1795) तक शासन किया। यह काल आज भी सुशासन और उत्कृष्ट व्यवस्था की दृष्टि से याद किया जाता है। आप एक बेहद संवेदनशील शासक और धर्मपरायण व्यवस्थापक थीं। अपने पूरे जीवनकाल में आप जनता के बीच बेहद सम्माननीय एवं लोकप्रिय शासक रहीं। महारानी अहिल्यादेवी होलकर को मध्यप्रदेश के मालवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भी सम्मान से राजमाता एवं देवी कहकर ही सम्बोधित किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी आप इंदौर राजघराने की बहू बनीं।

अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड में चोंडी गांव में एक धनगर जाति के परिवार में हुआ था। राजमाता अहिल्यादेवी में बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व विकसित हो गया था एवं आप सनातनी हिंदुत्वनिष्ठ महारानी के रूप में विख्यात हुईं। विदेशी आक्रांताओं ने भारत के कई तीर्थस्थलों को नष्ट कर दिया था एवं मुगलों ने मंदिरों को तोड़ दिया था। अपनी तीर्थयात्राओं के दौरान मंदिरों की यह स्थिति उनसे देखी नहीं गई और आप उनके जीर्णोद्धार में जुट गईं। आपने न केवल इंदौर नगर बल्कि मालवा राज्य की सीमाओं के बाहर पूरे भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों (अयोध्या, हरिद्वार, कांची, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, काशी, गया, मथुरा सहित) पर मंदिर, घाट, कुओं, बावड़ियों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों आदि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया। जिनकी शिल्पकला आज भी उल्लेखनीय मानी जाती है।

राजमाता ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया था। आपने गोहाड का क़िला जीतकर युद्ध में अपनी प्रथम जीत दर्ज की। उनकी धार्मिकता के बाद जनता ने उनकी वीरता भी देखी। वे एक साहसी योद्धा और बेहतरीन तीरंदाज थीं। आप हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गोंड्स से उन्होंने कई बरसों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा।

राजमाता की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव था सेना को राज्य से अलग करना। आपने अपने विश्वासपात्र सूबेदार तुकोजीराव होलकर को अपना सेनापति बनाया था, जिनके पास सेना की पूरी कमान थी वहीं राजमाता ने शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी खुद के पास रखी थी। आपने राज्य और अपने स्वयं के खर्चे को भी अलग किया यानि जो खर्चा वो खुद पर करती वो उनका अपना संचित धन रहता था और राज्य के बेहतरी के लिए खर्चा राजकोष से आता था। यानि शासन व्यवस्था में उस समय उन्होंने एक अलग स्तर की पारदर्शिता को स्थापित किया। आप न्याय के प्रति बहुत सजग रहीं एवं अपने राज्य में नियमबद्ध न्यायालय बनवाए। गावों में पंचायतों को न्यायदान के व्यापक अधिकार दिए। जब अहिल्या बाई होल्कर 70 साल की हुईं तो उनकी तबियत बिगड़ने लगी। 13 अगस्त 1795 को इंदौर में उनकी मौत हो गई। अहिल्या बाई को उनके अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। देश के आजाद होने के बाद साल 1996 में भारत सरकार द्वारा अहिल्या बाई को सम्मानित किया गया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए थे।

क्या बांग्लादेश की तर्ज पर आजाद होगा बलूचिस्तान

नीरज कुमार दुबे

बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार सहते सहते अब स्थानीय लोग तंग आ चुके हैं और बांग्लादेश की तरह आजाद होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत उनकी मदद वैसे ही करे जैसे कि पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का गठन करवा कर की थी। इसके लिए बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री नाएला कादरी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वह भारत सरकार के अधिकारियों से मिल कर समर्थन मांग रही हैं। साथ ही नाएला कादरी हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि वह बलूचों को पाकिस्तानियों के जुल्म से बचाये। निर्वासित बलूच प्रधानमंत्री नाएला कादरी ने भारत में विभिन्न मीडिया संस्थानों को दिये साक्षात्कारों में बलूचों पर हो रहे अत्याचार की जो दास्तां सुनाई है उसको सुनकर किसी के भी रौंगटे खड़े हो जायेंगे।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ की आबादी वाले पश्तून समुदाय पर जमकर अत्याचार होते हैं। पश्तून लोगों के साथ मारपीट, उन्हें गायब कर देने, उनके साथ बुरे बर्ताव और उनकी महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की घटनाएं आम हैं। देखा जाये तो पश्तूनी लोग पाकिस्तान के साथ कितनी भी मजबूती से खड़े रहें हों लेकिन वहां की सरकार उन्हें गद्दार मानती है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करती है। संघ प्रशासित कबायली इलाके जिसे फाटा भी कहा जाता है, वहां अक्सर कर्फ्यू लगा रहता है। इस इलाके में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात तो छोड़ दीजिये यहां के लोगों के घर-बार भी अक्सर तोड़ दिये जाते हैं और उनके सामान पर कब्जा कर लिया जाता है तथा उन्हें सड़कों पर जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि विदेशों में भी जहाँ-जहाँ पश्तून रहते हैं, वह लोग वहाँ-वहाँ की राजधानियों में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अक्सर विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखा जाये तो पाकिस्तान के इस समय जो हालात नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में स्वायत्त देश बनाने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान चार हिस्सों में बंट सकता है। इसमें से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान के कई नागरिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दुर्गति को देखकर यही लगता है कि हम

हिन्दुस्तान के साथ ही रहे होते। सोशल मीडिया पर निगाह डालेंगे तो पाएंगे कि कई पाकिस्तानी नागरिक तो अब सिंध प्रांत, बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को भारत में मिलाने के लिए भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं।

जहां तक निर्वासित बलूच प्रधानमंत्री की ओर से बलूचों पर हो रहे अत्याचार के बारे में दी गयी जानकारी की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बलूच लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए दशकों से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने मुल्क की स्वतंत्रता के लिए दुनिया के तमाम देशों में जा-जाकर समर्थन मांग रही हैं। उनका कहना है कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हैं कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएं। नाएला कादरी का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री से ही उम्मीदें हैं कि वह कुछ करेंगे। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में बलूच होना ही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह होता है। नाएला कादरी ने कहा कि हमें मारने और किस्म-किस्म के अत्याचार करने का जैसे पाकिस्तानी सेना और पुलिस को लाइसेंस मिला हुआ है। उन्होंने बताया है कि अब इस खेल में चीन भी शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया है कि बलूचों की बहन-बेटियों को पाकिस्तानी सेना के जवान सरेआम उठा ले जाते हैं और उनके साथ कई-कई दिन तक बलात्कार किया जाता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिक किसी जवान लड़की को नहीं छोड़ते, लड़कियों के शरीर को बुरी तरह नोंचा जाता है। डर के चलते लड़कियां स्कूल और कॉलेज नहीं जातीं। उन्होंने बताया कि बाजार में भी या तो घर के मर्द जाते हैं या बुजुर्ग महिलाएं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से क्षेत्र में किसी विदेशी पत्रकार या न्यूज चैनल, सोशल वर्कर या विदेशी प्रतिनिधि को नहीं जाने दिया जाता जिससे कभी सच सामने नहीं आ पाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बलूचों के वजूद पर और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इस सब पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नजर लगी रहती है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हम भारत से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे कई क्रांतिकारी नेताओं को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बनाया हुआ है और दुनिया में कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। ऐसे में हमें भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। बहरहाल, हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्सों में पहुंचने के बाद पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं उसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2016 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिये अपने भाषण में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के हालात की बात की थी और कहा था कि बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों ने उनके मुद्दे उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है।

हिन्द स्वराज

कांग्रेस और उसके कर्ता-धर्ता (भाग-3)

गतांक से आगे...

प्रश्न- यह आपने ठीक कहा। दादाभाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किये हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते यह बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाईबंद बनकर बैठे हैं; वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जायँ, तभी स्वराज्य की बातचीत की जाय। उन साहब के भाषणों से तो में ऊब गया हूँ।

उत्तर- आप ऊब गये हैं यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ-बापके ठंडे मिजाजसे ऊब जाते हैं और वे (माँ-बाप) अगर अपने साथ न दौड़े तो गुस्सा होते है, वे अपने माँ-बाप का अनादर करते हैं ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज्य भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठें, तो हम निकम्मे हो जायेंगे। जो प्रौढ़ और तजरबेकार हैं वे ही स्वराज्य भुगत सकते हैं, न कि बे-लगाम लोग। और देखिये कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिन्दुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया तब ऐसे कितने हिन्दुस्तानी थे? मैं तो खास तौरपर मानता हूँ कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिन्दुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिन्द के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे, ऐसी हिन्द के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए।

क्रमश: ...

जी-20: भारत ने आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण, भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया की वकालत की

कोलकाता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को यहां 'जी-20 भ्रष्टाचार निरोधक मंत्रिस्तरीय बैठक' के दौरान ''दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त'' बनाने की दिशा में काम करने, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने और उनकी पूंजी जब्त किए जाने पर जोर दिया। सिंह ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करते हैं क्योंकि वे न्याय से बचने के लिए देशों की कानूनी एवं वित्तीय प्रणालियों के बीच अंतर और मतभेदों का फायदा उठाने में सक्षम हैं।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ''भगोड़े आर्थिक अपराधी अपने देश में गंभीर आर्थिक अपराध करते हैं और गिरफ्तारी, अभियोजन या सजा की तामील से बचने के लिए किसी अन्य देश में भाग जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि इन आर्थिक अपराधों में धोखाधड़ी, कर चोरी, धनशोधन एवं गबन जैसी कई अवैध गतिविधियां शामिल हैं। सिंह ने कहा कि इन आर्थिक अपराधियों के कृत्य

शासन के कानून को कमजोर करते हैं, आर्थिक विकास को बाधित करते हैं और अकसर भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) कानून प्रवर्तन सहयोग, सूचना साझा करने की प्रक्रिया और पूंजी बरामदगी तंत्र से जुड़े अहम मामलों पर सर्वसम्मति बनाने में सफल रहा है। मंत्री ने कहा, ''जी20 के रूप में हमें अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर साहसी होने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार से निपटा जा सके। मुझे भरोसा है कि जी20 सदस्य देश प्रत्यर्पण तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सीमा पार वित्तीय आवागमन की बेहतर निगरानी के लिए इन सिद्धांतों को लागू करने के लक्ष्य से ठोस कदम उठाएंगे। इससे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसेगी।'' सिंह ने कहा कि भारत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रबल समर्थक रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता होने के नाते यह सुनिश्चित करना जी20 की जिम्मेदारी है कि ''हम भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया के हकीकत में बदलने तक इस लय को बरकरार रखें।'' मंत्री ने कहा, ''भ्रष्टाचार विरोधी मजबूत नीतियों को प्राथमिकता देकर और उन्हें लागू करके हम पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की शक्ति है जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सुसंगत बनाना, सूचना साझा की प्रक्रिया को तेज करना और सीमा पार जांच एवं अभियोजन को मजबूत करना शामिल है।'' सिंह ने पारस्परिक कानूनी सहायता के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ''जवाबदेही रिपोर्ट'' को अंतिम रूप देने की दिशा में किए गए काम को रेखांकित किया और कहा कि इसके निष्कर्ष एवं सिफारिशें अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने, वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने में देशों के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने और मजबूत करने में बहुत उपयोगी होंगी।

उन्होंने कहा, ''ये भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।'' सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का नजरिया ''भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण'' का भी मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का आधार हैं। सिंह ने कहा कि शासन के आधुनिकीकरण, दक्षता बढ़ाने और सेवा वितरण प्रक्रिया में सुधार से भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जी20 एसीडब्ल्यूजी ने भ्रष्टाचार से मुकाबले में लेखा परीक्षा की भूमिका पर अच्छी पद्धतियों का एक संग्रह तैयार करने में सराहनीय प्रगति की है।

राहुल गांधी चाहते हैं भारतीयों को सेना गोली मारे : भाजपा

नई दिल्ली। लोकसभा के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस ने मणिपुर मामले पर केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब घेरा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा सदन में कहा था कि मणिपुर के हालात खराब हैं और भारतीय सेना इसे दो दिन में नियंत्रित कर सकती है। राहुल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सेना का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। राहुल ने इन आरोपों को राजस्थान की एक सभा में भी दोहराया था।

अब राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया किया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राहुल की सोच तानाशाहों वाली है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि भारत माता की हत्या हो रही है, मणिपुर में दो समुदायों के बीच तनाव है, उनका भाषण भड़काऊ था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 2 दिन में इसे नियंत्रित कर सकती है, वह चाहते हैं भारतीय सेना भारतीयों को गोली मारे। राहुल गांधी की सोच लोकतांत्रिक नहीं है।

केंद्र ने मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बनर्जी ने कहा कि 'पीएम केयर्स फंड', राफेल सौदे, नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते हैं। उनकी टिप्पणी से कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जी-20 भ्रष्टाचार-रोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सख्त नीति है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री ''बिना किसी सबूत के विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि देश के गरीब लोग जीवित रहें''।

कांग्रेस पर आरोप मढ़कर मणिपुर पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते पीएम: हरीश रावत

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मढ़कर मणिपुर की विस्फोटक स्थिति पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने साथ बातचीत में यह भी कहा कि मणिपुर के संदर्भ में राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक बात की जिससे सरकार बेनकाब होती है, इसलिए लोकसभा में दिए उनके भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उससे वहां की स्थिति की गंभीरता परिलक्षित होती है।

मणिपुर में जो लोग प्रभावित हैं, इन बातों से उनको यह महसूस हो रहा है कि कोई उनके दिल की बात कर रहा है।'' उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी जी के जो

शब्द हैं वो पूरी तरह लोकतांत्रिक शब्द हैं और वो स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। उनकी बातों से सत्ता बेनकाब होती है, इसलिए उनकी बातों को कार्यवाही से हटा दिया गया और इसके खिलाफ अभियान भी चलाया गया।'' प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस पर किए गए प्रहार के बारे में पूछे जाने पर रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा, ''अगर सब अच्छा होता तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) जैसे लोगों का अवतार नहीं होता।' उन्होंने यह भी कहा, 'आप नौ साल से सत्ता में हैं और आज मणिपुर में जो विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है उसके लिए आप वर्षों पहले एक स्थिति विशेष में उठाए गए कदमों को लेकर बातें नहीं कर सकते। पहले पूर्वोत्तर में उग्रवाद एक आम बात था, स्थिति को संभालने के लिए हमने अपनी कई सरकारें तक गवां दीं।'' रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को मणिपुर शांत और सामान्य स्थिति में मिला था।

उन्होंने कहा, ''अगर आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप मढ़कर अपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप स्थिति सुधारिए।' प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में मणिपुर समेत उत्तर-पूर्व के राज्यों में वर्षों से व्याप्त विभिन्न समस्याओं के लिए कांग्रेस और इसके शासन वाली पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि पूर्वोत्तर में समस्याओं की एकमात्र जननी कांग्रेस है।

विरोधियों को शांत करने के लिए पुलिस को ज्यादा शक्ति: सिब्बल

■ शाह के विधेयक पर विपक्ष को आपत्ति

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक- 2023, भारतीय सुरक्षा विधेयक- 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पर विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी।

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना चाहता है और यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए क्रूर पुलिस शक्तियों के उपयोग की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे कानून लाने के पीछे सरकार का एजेंडा विरोधियों को चुप कराना है।

आपराधिक कानूनों में आमूल-चूल बदलाव करते हुए केंद्र ने शुक्रवार को आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए

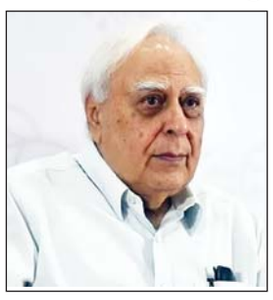

लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। जिसमें अन्य बातों के अलावा, राजद्रोह कानून को खत्म करने और अपराध की व्यापक परिभाषा के साथ एक नया प्रावधान पेश करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023; सीआरपीसी को बदलने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय सुरक्षा विधेयक विधेयक, 2023 पेश किया।

एक ट्वीट में राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा, भारतीय न्याय संहिता-2023 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, बीएनएस 15 से 60 या 90 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है। राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए नए अपराध (पुनर्परिभाषित)। यह विरोधियों को चुप कराने का एजेंडा है।

बीएनएस विधेयक मानहानि और आत्महत्या के प्रयास सहित मौजूदा प्रावधानों में कई बदलावों का प्रावधान करता है और छल से यौन संबंध बनाने के संबंध में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दायरे का विस्तार करता है। शाह ने कहा है कि त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए बदलाव किए गए हैं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मेरी यह मांग होगी कि वे इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें सभी दलों के प्रतिष्ठित कानूनी व्यक्ति शामिल हों। उन्होंने कहा कि पिछले बिल में जो प्रावधान थे, उनके मुकाबले प्रावधान दर प्रावधान और इनमें से प्रत्येक प्रावधान पर न्यायिक घोषणाएं क्या हैं इसकी जांच की जानी चाहिए।

■ मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक पर राजनीति हुई तेज

माई लॉर्ड, हमारे देश को बचा लो: ममता

कोलकाता। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इस बिल पर मोदी सरकार की निंदा की और निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अराजकता पर उतर आई है और वह न्यायपालिका को नहीं मानती है।

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्विटर पर कहा कि इस हफ्ते सीईसी की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल में सीजेआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं।

आगे सीएम बनर्जी ने कहा कि इस प्रक्रिया से असुविधा होगी और वोटों में हेरफेर हो सकता है जिससे नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं कि माई लॉर्ड हमारे देश को बचाइए।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े इस विधेयक पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह बिल दिखाता है कि प्रधानमंत्री संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को बदल देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा।

गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया था विधेयक विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 पेश किया था। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया। यह चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन की शर्तें अधिनियम, 1991 को निरस्त करता है।

इस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी सेवा शर्तों और पदावधि के बारे में नए नियम का उल्लेख है। इसके मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की तीन सदस्यीय समिति करेगी। इस चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा।

वैचारिक कारणों से अक्सर दी जाती है भारत के हितों की बलि: जयशंकर

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अक्सर कुछ वैचारिक कारणों के कारण भारत के हितों की बलि दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा देश के हितों को अपने मूल में रखते हुए दुनिया के साथ काम करेगी। आकाशवाणी के साथ एक साक्षात्कार में जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष युग से अधिक

मुखर और राष्ट्रीय हित-संचालित दृष्टिकोण में बदलाव पर प्रकाश डाला। जयशंकर ने गुटनिरपेक्षता के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए इसे ऐसे समय में भारत की स्वतंत्रता के दावे की अभिव्यक्ति बताया जब इसकी क्षमताएं सीमित थीं। उन्होंने कहा कि जहां गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति में एक विशिष्ट युग का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं यह अपनी सीमाओं के साथ भी आई है।

मंत्री ने कहा कि एक ऐसा युग था जहां हमारी क्षमताएं सीमित थीं और जहां हमने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को पहले नहीं रखा था। कभी-कभी हमें वह लाभ नहीं मिलता जो हमें मिल सकता था। लेकिन वह अतीत की बात है। 1990 के दशक के दौरान सामना की गई चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की अवधि, जयशंकर ने कहा कि इन सुधारों ने आर्थिक और राजनयिक रणनीतियों के बीच अटूट संबंध को पहचानते हुए, भारत की विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता की।

उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपनी आर्थिक नीति बल्कि अपनी विदेश नीति भी बदलनी होगी क्योंकि दोनों साथ-साथ चलते हैं। जयशंकर ने देश की बढ़ी हुई क्षमताओं, आत्मविश्वास और पर्याप्त वैश्विक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता में विश्वास को रेखांकित किया। आज, हम एक अलग युग में हैं - यह एक ऐसा युग है जहां हम अधिक सक्षम, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक महत्वाकांक्षी हैं, हमें लगता है कि हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह एक ऐसा समय भी है जो अधिक वैश्वीकृत है। ताकि चुनौतियाँ अलग हों, क्षमताएँ अलग हों, लक्ष्य अलग हों।

भारत ने श्रीनगर में तैनात किया अपग्रेडेड मिग-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन

■ पाक-चीन से निपटने की तैयारी

श्रीनगर। भारत ने पाकिस्तान और चीन मोर्चों के खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। %उत्तर के रक्षक% के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ट्राइडेंट्स स्क्वाड्रन ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर मिग-21 स्क्वाड्रन की जगह ले ली है। मिग-21 स्क्वाड्रन पारंपरिक रूप से पाकिस्तान से खतरे की देखभाल के लिए जिम्मेदार रहा है।

भारतीय वायु सेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने समाचार एजेंसी को बताया कि श्रीनगर कश्मीर घाटी के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। ऐसे में अधिक भार एवं चुनौतियों के अनुपात और सीमा के निकट होने के कारण कम प्रतिक्रिया समय वाला विमान रखना रणनीतिक रूप से बेहतर है। साथ ही यह बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। उन्होंने कहा, मिग-29 उन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है जिसके कारण हम दोनों मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लेने में सक्षम हैं। मिग-21 की तुलना में मिग-29 के कई फायदे हैं, जो कई वर्षों तक कश्मीर घाटी में अपनी जिम्मेदारी से क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम है और 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर एफ-16 को मार गिराने में भी कामयाब रहा है। अपग्रेड होने के बाद मिग-29 को बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से भी लैस किया गया है और सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी

गई आपातकालीन खरीद शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे घातक हथियारों से भी लैस किया गया है। अधिकारियों ने कहा, लड़ाकू विमानों को संघर्ष के समय दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम करने की क्षमता भी प्रदान की गई है। एक अन्य पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने कहा कि उन्नत विमान रात में नाइट विजन चश्मे के साथ काम कर सकता है और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज भी लंबी है। उन्होंने कहा, हमने हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों को भी शामिल किया है, जो पहले नहीं था। विमान की सबसे बड़ी क्षमता पायलट हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा इन विमानों पर सेवा देने के लिए चुना जाता है। मिग-29 इस साल जनवरी में श्रीनगर एयर बेस पर आए थे और लद्दाख सेक्टर के साथ-साथ कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर उड़ान भरी थी। यहां से वे चीन द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के किसी भी प्रयास के मामले में प्रतिक्रिया देने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। मिग-29 पहला विमान था जिसे 2020 के गलवां संघर्ष के बाद चीनी पक्ष से खतरे से निपटने के लिए लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया था और तब से ऐसे कई प्रयासों को विफल किया गया है।

गुलामी की हर निशानी मिटाने मोदी सरकार के फैसले को कानूनी विशेषज्ञों ने सराहा

नईदिल्ली। औपनिवेशिक युग की हर निशानी मिटाने को आतुर मोदी सरकार की ओर से गुलामी काल के कानूनों- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- को बदलने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने के केंद्र के कदम का कानूनी विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों ने, हालांकि उन्हें हिंदी में नाम देने को लेकर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में ब्रिटिशकालीन आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए तीन नये विधेयक पेश किये और कहा कि अब राजद्रोह के कानून को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किये। ये क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की समकालीन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखने वाली एक कानूनी प्रणाली बनाने के लिए ये परिवर्तन किए गए।

इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आर.एस. सोढ़ी ने कहा कि भारत एक विकासशील और जीवंत समाज है जिसमें कोई भी स्थिर कानून नहीं रख सकता है। सरकार के कदम पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सोढ़ी ने कहा कि जहां भी बदलाव की जरूरत है, उसे लाया जाना चाहिए और जो भी कानून समाज की भलाई के लिए है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''एक जीवंत समाज में, कानूनों को भी बदलना होगा। आपके पास स्थिर कानून नहीं हो सकते।'' छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने

के प्रस्तावित प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सोढ़ी ने कहा, छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी को छोटी-छोटी बातों पर जेल भेजने से किसी को मदद नहीं मिलती।%

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और विकास पाहवा ने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक युग के अप्रचलित कानून थे और उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता थी। विकास सिंह ने सरकार के इस कदम पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, यह ऐसी चीज है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने हालांकि इन विधेयकों का नाम हिंदी में रखने का मुद्दा उठाया और कहा कि इन कानूनों के नाम हिंदी में नहीं होने चाहिए क्योंकि यह अदालतों की आधिकारिक भाषा नहीं है। विकास सिंह ने कहा कि जो लोग हिंदी से परिचित नहीं हैं, उन्हें इन प्रस्तावित अधिनियमों के नाम समझने में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा, मैंने विधेयकों को विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन कम से कम नाम बदलना उस न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से निरर्थक है, जो काफी हद तक अंग्रेजी भाषा पर चलती है, खासकर उच्चतम न्यायालय में जहां यह संविधान द्वारा प्रावधानित है कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है। उनकी बात का समर्थन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नामकरण में ये बदलाव निरर्थक हैं। गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, ''इन कानूनों के नामों को हालांकि हिंदी शब्दों से बदलना उस न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से अर्थहीन है, जो ज्यादातर अंग्रेजी में चलती है।

ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों के खिलाफ एक प्रमुख आवाज रहे वकील जे. साई दीपक ने कहा कि उन्होंने, हालांकि विधेयकों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उन्हें खुशी है कि कम से कम इन कानूनों के नाम बदल दिए गए हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा, तीन प्रमुख आपराधिक अधिनियम सौ साल से भी पहले लागू किए गए थे और इनमें संशोधन की सख्त जरूरत थी। फौजदारी मामलों के वकील के रूप में, मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुकदमे की प्रक्रिया, दंडात्मक अपराधों की परिभाषा और साक्ष्य के कानून पुराने हैं, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है और आधुनिक भारत के साथ तालमेल बिठाना होगा। इस तर्ज पर बनाया गया कोई भी कानून हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अनुकूल होगा।

शनि चल रहें हैं नाराज तो इन मंत्रों का जरूर करें जाप

शनि के ये मंत्र खोलेंगे किस्मत के दरवाजे

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है। वहीं शनि देव को न्यायप्रधान भी कहा जाता है। क्योंकि शनि देव भक्तों को उनके कर्मानुसार शुभ-अशुभ फल देते हैं। जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे इसके लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिन भक्तों को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वह रंग से भी राजा बन जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं।

शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए कुछ विशेष मंत्रों के बारे में बताया गया है। इन मंत्रों का जाप शनिवार के दिन करने से कुंडली में शनि ग्रह शांत होते हैं और शनि की साढ़े साती व ढैया का प्रभाव कम होता है। साथ ही जो भक्त श्रद्धाभाव से इन मंत्रों का जाप करते हैं। शनि देव उन पर कृपा बरसाते हैं।

शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए करें इन मंत्रों का जाप

शनि बीज मंत्र- ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

शनि महामंत्र- ॐ निलान्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम।।

शनि का वैदिक मंत्र- ऊँ शन्नोदेवीर-भिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तुनः।

शनि गायत्री मंत्रए- ऊँ भगभवाय विद्महैं मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात्।

तांत्रिक शनि मंत्र- ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

शनि दोष निवारण मंत्र- ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात।।ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।शंयोरभिश्रवन्तु नः। ऊँ शं शनैश्चराय नमः।।

इस विधि से करें मंत्र का जाप -

शनिवार के दिन स्नान आदि करके काले रंग के कपड़े को धारण करें। इसके साथ ही काले रंग से मिलता-जुलता रंग जैसे स्लेटी रंग, बैंगनी रंग पहनें।

शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर नीले रंग का फूल चढ़ाएं। कुश के आसन पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

किस आंख का फड़कना महिलाओं और पुरुषों के लिए शुभ या अशुभ माना जाता है

आंख का फड़कना शुभ या अशुभ?

आंख का फड़कना बेहद ही आप बात है। आपने अक्सर लोगों को आंख फड़कने की शिकायत करते सुना होगा। कुछ मिनट के लिए लोगों को ये दिक्कत आती है, लेकिन अपने आप ये दिक्कत ठीक भी हो जाती है। हिंदू धर्म में आंख फड़कने को शुभ या अशुभ संकेत से जोड़ कर देखा जाता है।

महिलाओं में आंख फड़कना

आंख फड़कना एक आम बात है। लेकिन हिंदू धर्म में आंख का फड़कना महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग नजरिए से देखा जाता है। महिलाओं के लिए बाईं आंख के फड़कने को शुभ शगुन के रूप में देखा जाता है। अगर किसी महिला की बाईं आंख फड़कती है तो इसका अर्थ है उसे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं बाईं आंख का फड़कना महिलाओं में शुभ नहीं होता। इसका अर्थ है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर कोई दुर्घटना होने वाली है।

पुरुषों में आंख पड़कना

वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में दाहिनी आंख का फखड़ना शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है अगर आपकी दाहिनी आंख फड़क रही है तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वहीं पुरुषों में बाईं आंख का फड़कना शुभ नहीं माना जाता।इसका अर्थ है आपके साथ आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है।

वैज्ञानिक कारण

ऐसा माना जाता है कि जब बहुत ज्यादा आंखों पर स्ट्रेस देते हैं या आपकी नींद ना पूरी हुई हो या दिमाग में टेंशन हो, या फिर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो उस वजह से आपकी आंख फड़ती है। इसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में दिक्कत होती है, यही कारण बन जाता है आपकी आंख फड़कने का और आपको आंखों में परेशानी झेलनी पड़ती है।

समस्याएं देती हैं मजबूत होने के संकेत

जानें गीता के अनमोल विचार

श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है।

गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है।श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्रीकृष्ण ने बताया है कि जीवन में आने वाली समस्या किस चीज का संकेत देती है।

गीता का ज्ञान

गीता के अनमोल वचन

-गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं।

-गीता में श्रीकृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताते हुए कहा है कि, गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए, वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो- यही धर्म है।

-गीता में लिखा है कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है जबकि स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है।

अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय आता है।

डर हटाने का एक मात्र उपाय स्वधर्म को पहचान कर उसमें जीना है।

-श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य! यह शरीर नश्वर हैं पर आत्मा अमर है। इसलिए इस नश्वर शरीर पर घमंड करना बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए।

-आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर कीमत पर प्रसन्न ही रहेंगे। वहीं आप मन में बार-बार नकारात्मक विचार लाते हैं, तो आप दुखी रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है।

-गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को अकेले चलने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए।

पुण्यफलदायी है परमा एकादशी

इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जोकि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिकमास लगने से 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के अलग-अलग नाम और महत्व होते हैं।

परमा एकादशी का व्रत तीन साल में एक बार रखा जाता है। यह उस साल होता है, जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है। इस बार सावन में अधिक मास लगा है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जोकि शनिवार 12 अगस्त 2023 को पड़ रही है।

परमा एकादशी 2023 कब है

कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आरंभ: शुक्रवार 11 अगस्त सुबह 05:06

कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि समाप्त: शनिवार 12 अगस्त सुबह 06:31

हिंदू धर्म में उदयातिथि का महत्व होता है और इसके अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए था। लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को मान्य होगा।

परमा एकादशी 2023 कथा

परमा एकादशी व्रत कथा

काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते हैं। ब्राह्मण बहुत धर्मात्या था और पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी। लेकिन पूर्व में किए किसी पापी के कारण दंपती गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी-कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दंपति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति-पत्न घोर निर्धनता में अपना जीवन बिता रहे थे।

तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा: हे प्रिय! जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती। इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेस जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी! अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वसुर और सगे-सम्बंधी सभी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए स्वामी कृपा करके आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा, हमें वह यहीं से प्राप्त हो जाएगा।

पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया और परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपती गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। कुछ समय बाद वहां कौण्डिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। दंपति ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नि के ऋषि से कहा- हे ऋषिवर! कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहां आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि, अब हमारी दरिद्रता जल्द ही नष्ट हो जाएगी।

कौण्डिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है। क्योंकि यह एकादशी धन-वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी।

इसके बाद कौण्डिन्य ऋषि ने दंपति को परमा एकादशी व्रत के विधान बताए। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो पांच दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता-पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पांच दिन तक केवल संध्या भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं, जो स्नान करके पांच दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य पाते हैं, जो इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है, जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षो तक विष्णुलोक में वास करते हैं, जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं, जो पांच दिन तक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सिद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी।

कौण्डिन्य ऋषि के कहेनुसार, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का पांच दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्माजी की प्रेरणा से उसे सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से दंपति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्रीविष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ।

बुलंद रहे धर्म की पताका

धर्म एक आदत के समान है। इसका स्वयं पालन करना आवश्यक है, लेकिन दूसरों को पालन करवाने के लिए ज़बरदस्तीकरना नहीं चाहिए। धर्म का विस्तार धर्म के अनुसार ही होना आवश्यक है यदि आप धर्म के विस्तार के लिए अधर्म कर रहे हैं तो आपका धर्म पहले ही नष्ट हो चुका है। धर्म का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस समाज में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। धर्म व्यक्ति के मष्तिष्क से मोह-माया को समाप्त कर उन्हें जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत करवाता है। धर्म विश्वास पर आधारित है कृपया इसका आधार अंधविश्वास को ना बनाएँ। धर्म की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है मानव हानि के लिए नहीं। अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही अपने धर्म को निभाना है। मानव धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। उपरोक्त बातों पर गहन विचार करने के बाद हमें लगा कि आज-कल के भाग-दौड़ भरे जीवन में पर्व और तिथियाँ याद रखना चुनौती बन गया है। इसलिए आपकी चुनौती का समाधान करने का बीड़ा हमने उठाया है। इसके तहत पाठकों को प्रतिदिन के व्रत-त्योहार की जानकारियाँ एक जगह समेट कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं।

– संजना अग्रवाल

संक्षिप्त समाचार

विस चुनाव से पहले भाजयुमो की जिला कार्यकारिणी घोषित, शंकर बने जिला मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की लंबी लिस्ट जारी की गई है। जारी सूची में शहर से ग्रामीण तक हर एक वर्ग के युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। रायपुर जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री

की कमान शंकर साहू को सौंपी गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष समेत विशेष आमंत्रित सदस्यों को नियुक्त किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही है. ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम कर सकें। रायपुर जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में राहुल रॉव, आशीष आहूजा, राहुल यादव, अश्विनी विश्वकर्मा, अनिल शर्मा को जिमेदारी दी गई है। जिला महामंत्री के पद पर प्रणय साहू और अर्पित सूर्यवंशी को नियुक्त किया गया है। इसी तरह जिला मंत्री, कार्यालय मंत्री , विशेष सदस्यों में भी बड़ी नियुक्तियां की गई है।

मतदाता जागरूकता के लिए सीपीएम कालेज में छात्राओं ने बनाई रंगोली

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला प्रशासन के निर्देश पर मतदाता जागरूकता (स्वीप) अभियान अंतर्गत सीपीएम कालेज सारंगढ़ में स्वीप रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्राओं ने सामूहिक रूप से कालेज परिसर में चुनई चिरई, मतदान चिन्ह, नारा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ सब्बो जाबो वोट देहे बर, छोड़कर सारे काम पहले करे मतदान, आओ मतदान करें, मेरा मतदान मेरा अधिकार, छत्तीसगढ़ के नक्शे के साथ मतदान का अधिकार का प्रतीक स्याही से रंगे हुए अंगूठे की रंगोली बनाई गई।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, भूपेश सरकार देगी 50 हजार रुपए का स्कॉलरशिप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 के तहत वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी। मेरिट सूची में नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे और विकलांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023 को स्वीकृत कर दी है। ये योजना निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वालों के लिए है। प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होने के बाद भी पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे छात्र-छात्रों के लिए ये योजना लागू किया गया है। नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम के लिए शासकीय एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है।

चेम्बर भवन में होगा राष्ट्रीय ध्वजारोहण

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय चै.देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट में 15 अगस्त को प्रातः ठीक 9.30 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित है। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने दी।

छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन का पुनर्गठन, दिलीप षड़ंगी होंगे अध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के स्पॉट ब्वॉय से लेकर प्रोड्यूसर की परेशानियों को दूर करने छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन का पुनर्गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ी गायक दिलीप षड़ंगी व प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भारती वर्मा, अभिनेत्री अनिकृति चौहान और ज्योत्सना ताम्रकार को ट्रस्टी में जगह दिया गया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिलीप षड़ंगी ने बताया कि एसोसिएशन के जरिए छॉलीवुड में काम करने वाले कलाकारों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की जाएगी तथा छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने, राज्य के कलाकारों को नियमित रोजगार देने, फिल्म निर्माण के लिए सरकार से सब्सिडी मांगने, शूटिंग के लिए सस्ती दरों पर लोकेशन उपलब्ध कराने, फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में ज्यादा से ज्यादा शोज और स्क्रीनिंग देने जैसे एजेंडे पर काम किया जाएगा। एसोसिएशन के जुड़े देशमुख ने कहा कि इन दिनों फिल्म पॉलिसी का फायदा उठाने बॉलीवुड लगातार छत्तीसगढ़ का रुख कर रहा है और बॉलीवुड के लोग यहां आकर फिल्म तो शूट कर देते हैं लेकिन यहां के कलाकारों को वाजिब मेहनताना नहीं देते। हमारे बायलाज में यह प्रावधान है कि मुंबई या छत्तीसगढ़ से बाहर के मेकर्स हमसे एनओसी ले फिर यहां शूटिंग करे। इसके लिए हमने पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत को ज्ञापन भी सौंपा था। पत्रकारवार्ता में मनु नायक, डॉ. गौरव शर्मा, गजेन्द्र रथ वर्मा, राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

धान खरीदी को लेकर बघेल सरकार पर भाजपा का हमला

विष्णु देव साय बोले- मिलकर लड़ेंगे चुनाव, खत्म होगा वनवास

अंबिकापुर। अंबिकापुर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की दर 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा कर सकती है। भाजपा के चुनाव घोषणापत्र समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में जब समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल था, तब कांग्रेस ने 2500 रुपये प्रतिक्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा की थी, अब धान का केंद्रीय समर्थन मूल्य 2184 रुपये है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों से 3000 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाना चाहिए। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है।

शनिवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मोदी सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। इसे

ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी का 80 फीसदी राशि दी जा रही है। इसमें 20 प्रतिशत राशि देकर प्रदेश सरकार धान खरीदी का श्रेय ले रही है और झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने पर सहमत हो गई है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं है। प्रदेश में कुल 40.78 लाख किसान हैं लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि मात्र 22 लाख किसानों को मिल पा रही है। प्रदेश के 18 लाख से अधिक किसानों को यह राशि नहीं मिलने के लिए प्रदेश सरकार दोषी है।

पीएम के नाम भेजेंगे पोस्टकार्ड

विष्ण देव साय ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के निर्णय से प्रदेश में किसानों का पूरा धान खरीदा जा सकेगा। इससे किसानों को फायदा होगा। इस निर्णय को किसानों तक भाजपा पहुंचाएगी और भाजपा को इसका लाभ होगा। किसानों के माध्यम से पीएम मोदी के नाम धन्यवाद पत्र पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा।

एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, सीएम का निर्णय करेगा सेंट्रल बोर्ड

भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णु देव साय से यह पूछे जाने पर कि क्या वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? साय ने कहा कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भाजपा का सेंट्रल बोर्ड करेगा।

जल्द खत्म होगा वनवास

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्ण देव साय ने कहा कि प्रदेश में 15 वर्ष तक सत्तासीन रही भाजपा के शासनकाल में किसानों के हित में कई बेहतर निर्णय लिए गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धान खरीदी व चावल योजना में शायद कोई कमी रह गई थी, इसलिए भाजपा को वनवास मिला, लेकिन यह वनवास लंबा नहीं है। पांच साल का वनवास जल्द समाप्त होगा।

शहर के दो च्वॉईस सेंटर तीन माह के लिए ब्लॉक

रायपुर। शहर के दो च्वॉईस सेंटरों पर अवैध वसूली कर सेवाएं प्रदान करने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन द्वारा तीन माह के लिए आईडी ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई है। अब तीन माह तक पारस च्वॉईस सेंटर महोबा बाजार और टिकरापारा साहू काम्पलेक्स स्थित आल इन वन च्वॉईस सेंटर द्वारा शासकीय सेवाओं से संबंधित किसी प्रकार के काम नहीं किए जा सकेंगे। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे के निर्देश पर इन दोनों च्वॉईस सेंटरों का आकस्मिक निरीक्षण भी अधिकारियों ने किया था। इस बारे में जिला ई-गर्वेन्स सोसायटी की मैनेजर कीर्ति शर्मा ने बताया कि स्थानीय समाचार पत्रों में महोबा बाजार के पारस च्वॉईस सेंटर तथा टिकरापारा साहू काम्पलेक्स के आल इन वन च्वॉईस सेंटर के विरूद्ध अवैध रूप से राशि लेकर बी.पी.एल. कार्ड बनाने की खबरें प्रकाशित हुई थी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। दोनों लोक सेवा केन्द्रों की जांच अधिकारियों द्वारा दी गई थी। इस दौरान दोनों केन्द्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में ऑनलाईन नहीं पाए गए। इसके साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजनाओं से जुड़ी जन-सुविधा की सेवाएं आय, जाति, निवास इत्यादी बनाने की सेवा शुल्क की जानकारी भी केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। इन केन्द्रों पर जन-सुविधा सेवाओं से संबंधित कोई पंजी या रिकार्ड भी नहीं रखा गया था। जनहित की सेवाएं देने में लापरवाही बरतने पर दोनों च्वॉईस सेंटरों की आई.डी. आगामी तीन माह के लिए ब्लॉक कर दी गई हैं।

रोजगार देने में मिलती है बेरोजगारी भत्ता से ज्यादा खुशी : मुख्यमंत्री

■ व्याख्याताओं को मिला नियुक्ति पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर अपने निवास कार्यालय में शिक्षक भर्ती-2023 के व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान हायर सेकेंडरी सह आईटीआई ट्रेड के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सीएम के निर्देश पर हायर सेकंडरी के साथ ही आईटीआई कोर्स शुरू किया गया है। सीएम ने प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 12वीं के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने आज प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी रोजगार देने में मिलती है। विशेष भर्ती

अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है।

इसके पहले सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। युवाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देने और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं की अपार क्षमता और जीवन शक्ति की याद दिलाता है। एक स्थायी और समावेशी भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव और युवाओं से भेंट-मुलाकात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की पहल की गई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, हरित संक्रमण की दिशा में यात्रा शुरू करना रखी गई है। इससे युवाओं में सामाजिक भागीदारी और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ के 29 लोग 15 अगस्त को लाल किले में सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी को

रायपुर। इस वर्ष 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में पूरे देश से लगभग 1,800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से पांच किसान उत्पादक संगठणों के प्रतिनिधी के साथ करीबन 29 मान्यवरों को आमंत्रित किया गया है।

इस वर्ष भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में मदद करने वाले श्रम योगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और जिन लोगों ने देश के विभिन्न भागों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं में सहायता और काम किया है, उन्हें इस साल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ आमंत्रित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के यह 29 लाभार्थी, अपने परिवारों के साथ, लगभग 1,800 व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरे भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनने की यह पहल सरकार द्वारा जनभागीदारी के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। छत्तीसगढ़ से अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत रायपुर से 45 किलोमीटर दूर आरंग विकासखंड के गोइनदा दा गांव के सरपंच संतोष कुमार साहू और मजदूर के तौर पर कार्य करने वाले माधव राम निषाद विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त, 2023 को ऐतिहासिक लाल किले, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। गोइनदा दा गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब का गहरीकरण किया गया एवं उसे स्वच्छ बनाया गया ताकि लोग उस तालाब के पानी को अपने उपयोग में ला सके इस तरह गांव का तालाब स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा एवं ग्राम में रहने वाले नागरिक को रोजगार भी उपलब्ध हुई। इस सराहनीय कार्य में सहयोग करने के लिए इन दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। इस बारे में गांव के सरपंच संतोष कुमार साहू ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: मोहन मरकाम

■ प्रभारी मंत्री मरकाम ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की मैराथन बैठक

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग एवं मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहन मरकाम ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ सभी को मिले। जनता को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के मंशानुसार व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र धारियों को मनरेगा के अंतर्गत भूमि समतलीकरण व अन्य कार्य प्राथमिकता से स्वीकृत किया जा रहा है। इससे वनाधिकार

पत्र धारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। किसी भी कारण से अस्वीकृत वनाधिकार पत्रों को फिर से रिव्यू किया जाए और पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र वितरित करने के निर्देश दिए। इसी तरह राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के सम्बन्ध में जनता के बीच प्रतिक्रिया से अवगत होते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी से जिले में खाद-बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। खाद्य बीज की काला बाजारी को रोकने के लिए सतत् रूप से दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने उप संचालक कृषि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा अन्य योजनाओं से अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने को कहा। गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए श्री मरकाम ने जिले के गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पाद व गौठानों में कार्यरत स्व.-सहायता समूहों की जानकारी ली तथा अधिक से अधिक महिला स्व-सहायता समूह को जोड़ने के निर्देश दिये। इसी तरह जिले मे रीपा अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेते हुए क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक स्व-रोजगार से जोड़ने को कहा।

भूपेश सरकार ने 36 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया : भाजपा

■ खुली बहस करने भाजपा कार्यकर्ता तैयार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की मार्कशीट आ गई है जिसमें अधिकतर को जीरो नंबर मिला है और यह हम नहीं, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में मीडिया में पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पूरे प्रदेश ने पढ़ा और सुना है।

शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के फेल्योर का बड़ा घाटा प्रदेश की जनता को हुआ है, यह बड़ा मसला है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी उपस्थित थे। शर्मा ने कहा कि जितनी बड़ी सरकार होती है, उतनी ही बड़ी एंटी इन्कम्बेंसी होती है और एंटी इन्कम्बेंसी तब और बढ़ जाती है, जब अकर्मण्य विधायक होते हैं। कांग्रेस के अधिकांश विधायक विफल सिद्ध हो गए हैं और आने वाले चुनाव में यह बात सिद्ध हो जाएगी। अभी हाल ही में अनिच्छापूर्वक उपमुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रहा है। यह बात केवल उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने ही नहीं कही, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री बघेल ने भी अपने एक बयान में कहा था कि विधायकों को बदला जाएगा, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। प्रदेश प्रभारी रहते हुए पीएल पुनिया ने भी यह बात कही थी कि विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के जिन नेताओं और बड़े पदाधिकारियों ने अपने विधायकों के परफॉर्मेंस को देखा, उस आधार पर यह निर्णय आता है कि कांग्रेस के विधायक फेल हो चुके हैं और इनकी मार्कशीट में शून्य अंक नजर आ रहा है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने जनता की वह सेवा नहीं की, जिसके लिए जिसके लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। यूँ भी पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए 36 में से एक वादा भी प्रदेश की भूपेश सरकार ने पूरा नहीं किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के किसी भी नेता, मंत्री, पदाधिकारी के साथ कभी भी और कहीं भी बहस करने के लिए भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता तैयार है।

लता उसेंडी ने बघेल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, मची सियासी खलबली

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में बस्तर से सत्ता की चाबी मिलती है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में जो आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी बघेल सरकार की महत्वकांक्षी योजनाल नरवा गुरुवा घुरवा बाड़ी के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। इस योजना के बहाने बीजेपी बघेल सरकार पर गौठान और गोबर घोटाले का आरोप लगा रही है।इसके अलावा किसानों और धान खरीदी के मुद्दे पर भी बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से कोंडागांव की पूर्व विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने बघेल सरकार पर अटैक किया है। उन्होंने बघेल सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

बघेल सरकार किसानों के साथ कर रही धोखा

बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों को छलने का काम कर रहे हैं। जिन किसानों ने

भूपेश बघेल को सीएम बनाने का काम किया है। उन्हीं को बघेल सरकार धोखा दे रही है। मौजूदा सरकार ने किसानों के धान का रकबा कर दिया है। समितियों के माध्यम से घटिया खाद खरीदने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है।

गौठान घोटाला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला

लता उसेंडी ने बघेल सरकार पर गोबर खरीदी को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर गोबर खरीदने की झूठी वाहवाही लूट रही है जबकि गौठान में स्थिति बिल्कुल उलट है। गौठानों में ना मवेशी है ना ही गोबर खरीदी हो रही है। गोबर खरीदी का झूठा आंकड़ा दिखाकर फर्जीवाड़ा कर रही है। महिला समूहों के बनाए घटिया वर्मी कंपोस्ट को किसानों को बेचा जा रहा है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच की गई तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा।

अमानक खाद की होगी जांच

बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है कि किसानों को अमानक खाद जबरदस्ती दिया जा रहा है। हमने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बीजेपी नेता पवन साहू ने इस मसले पर बताया कि जिला प्रशासन ने यह भरोसा दिया है कि सभी के वर्मी कंपोस्ट का परीक्षण कराया जाएगा। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी।

पवन साहू का आरोप है कि किसानों को मिट्टी और पत्थर मिलाकर घटिया वर्मी कंपोस्ट दबावपूर्वक दिया जा रहा है। किसानों से छल करने वाली इस सरकार के गिनती के दिन बच चुके हैं।

लता उसेंडी ने कहा भूपेश बघेल जी गौठान तो खोल दिए हैं। हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है जो स्कीम तो बनाती है। लेकिन बजट नहीं देती है। बिना बजट के योजना चलाने वाली सरकार है।

कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप

भाजपा के आरोपों को एक बार फिर कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपाइयों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए चुनावी स्टंट के तहत अफवाह फैलाने का काम कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने कहा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के लिए उत्कृष्ट योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका फायदा यहां के किसानों को हो रहा है। ना सिर्फ किसान बल्कि हर वर्ग कांग्रेस की योजना का लाभ उठा रहा है।

बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

आने वाले चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस घोषणापत्र बनाने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि साल 2018 में कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल किए गए 36 बिंदुओं ने प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाई। कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान सबसे प्रमुख थे। इसी की तर्ज पर भाजपा भी साल 2023 विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू का कहना है कि 20 क्विंटल से भी ज्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जिसे घोषणा पत्र में शामिल करने पर लगातार चर्चा चल रही है।

भाजपा ने संकेत दे दिया है कि उनके घोषणा पत्र में किसानों पर खास फोकस होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी अपने घोषणा पत्र में किसानों को टॉप पर रखती है या नहीं।

आईएएस अफसरों की फटाफट बदलती पोस्टिंग

लगता है भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों को पिच में जमने नहीं देना चाहती है। अफसरों के विभागों में जल्दी-जल्दी बदलाव से तो यही लगता है। यह तो सरकार का विशेषाधिकार है कि किस अफसर से क्या काम ले और कितने दिन तक वहां पदस्थ रखे, लेकिन कहते हैं अफसरों के विभागों में जल्दी-जल्दी हेरफेर से मंत्रालय के स्टाफ का सिर दर्द बढ़ गया है, वहीं मातहत अफसर और आम लोग भी उलझने लगे हैं। पुराने बॉस को समझने से पहले ही मातहत अफसरों को नया बॉस मिल जाता है। अफसर भी विभाग को समझने की कोशिश करते हैं उसके पहले उनका विभाग बदल जा रहा है। कुछ महीने पहले ही आईएएस सारांश मित्तर को संचालक उद्योग और सीएसआईडीसी का प्रबंध संचालक बनाया गया था। अब ये दोनों महकमा आईएफएस अरुणप्रसाद पी को दे दिया गया है। अरुणप्रसाद पी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव हैं।सरकार ने अरुणप्रसाद पी की जगह ही सारांश मित्तर को सीएसआईडीसी का प्रबंध संचालक बनाया था। हाल के फेरबदल में सारांश मित्तर का बोझ काम हुआ तो अरुणप्रसाद पी की जिम्मेदारी बढ़ गई। एक पखवाड़े पहले भी कुछ अफसरों के विभागों में हेरफेर किया गया था।

रवि भोई

मंडल को हटाना चर्चा में

पूर्व मुख्य सचिव आर पी मंडल को एनआरडीए के अध्यक्ष पद से हटाना चर्चा का विषय बन गया। वैसे अब एनआरडीए उपजाऊ संस्था रही नहीं, पर आर पी मंडल के लिए रिटायरमेंट के बाद एक ठौर था। आमतौर पर एनआरडीए के जिम्मे जो काम है, वह आर पी मंडल के अनुकूल था, वे नए रायपुर के साज-सज्जा में कुछ नए प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन तीन साल पूरा होने से पहले उनकी विदाई लोगों को चौंका रहा है। आर पी मंडल से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे अजय सिंह राज्य योजना मंडल और सुनील कुजूर सहकारिता आयोग में अभी बने हैं। सरकार ने अब एनआरडीए के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रिटायर्ड आईएफएस अफसर श्यामसुंदर बजाज को सौंपी है। कुछ साल पहले तक कांग्रेस सरकार की आंख की किरकिरी रहे बजाज साहब की एनआरडीए में वापसी हुई है। एस एस बजाज एनआरडीए के उपाध्यक्ष और सीईओ रह चुके हैं। नए रायपुर की संरचना में बजाज साहब का बड़ा योगदान है। इस कारण आर पी मंडल के विकल्प के रूप में श्यामसुंदर बजाज को चुना गया। एस एस बजाज अभी छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक हैं। वे अब दोनों काम साथ-साथ देखेंगे।

पूर्व मंत्री का गिफ्ट पॉलिटिक्स

कहते हैं एक भाजपा नेता और पूर्व मंत्री 2023 में जीत सुनिश्चित करने के लिए धूमधड़ाके से काम करना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि पूर्व मंत्री ने अपने विधानसभा इलाके के लोगों को कांसे की थाली और कटोरी उपहार में दे रहे हैं। थाली और कटोरी में बकायदे कमल निशान प्रिंट कराया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पूर्व मंत्री जी ने राजनीतिक गोटियां चली थीं, जिसके चलते उनकी नैया पार लग गई थी। अब देखते हैं इस बार भाजपा नेता क्या दांव खेलते हैं और उपहार पॉलिटिक्स क्या नतीजा निकलता है। वैसे भाजपा में कई चेहरे बदलने की चर्चा है। पुराने लोगों की जगह नए लोगों को मैदान में उतारने की भी बात चल रही है, लेकिन टिकट मिलने से पहले पूर्व मंत्री जी की तैयारी से तो लग रहा है कि उनको प्रत्याशी बनने से कोई रोक नहीं सकता।

बाजी पलटने भाजपा के कदम

कहते हैं भाजपा कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में कर सकती है। ये ऐसी सीटें हैं, जहां से भाजपा प्रत्याशी अब तक कभी नहीं जीते हैं। इसमें सीतापुर,कोंटा, मरवाही, पाली तानाखार और कुछ सीटें चर्चा में हैं। संयुक्त मध्यप्रदेश में मरवाही सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी, फिर वह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने पर सहमति बन गई है। चर्चा है कि जल्दी प्रत्याशी घोषित की जाने वाली सीटों के लिए दावेदारों के नाम भी बुला लिए गए हैं। खबर है कि 8 अगस्त को दिल्ली में अमित शाह के निवास पर हुई बैठक में शिवप्रकाश, ओम माथुर, डॉ रमन सिंह, अजय जामवाल, अरुण साव और पवन साय मौजूद थे।

लोगों के गुस्से का शिकार होते विधायक

कहते हैं लोगों में कांग्रेस सरकार से ज्यादा विधायकों को लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। पहली बार के विधायक जनता के निशाने पर ज्यादा बताए जाते हैं। कांग्रेस सरकार से अधिक विधायकों को लेकर गुस्सा का नमूना पिछले दिनों रायपुर में लोगों को देखने को मिला। क्षेत्र की जनता से मिलने गए विधायक जी के खिलाफ लोगों ने वापस जाओ के नारे लगा दिए। कहते हैं जनता के बीच मंच पर भाषण देते सरगुजा संभाग के एक कांग्रेस विधायक को भी उलटे पांव भागना पड़ा। 2018 की कांग्रेस लहर में विधायक बने अधिकांश लोगों की हालत पतली बताई जा रही है। माना जा रहा है पहली बार विधायक बने कई लोगों का कांग्रेस टिकट काट सकती है। अब देखते हैं क्या होता है ? चर्चा है कि इस बार कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी और बहू चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं।

सिंहदेव का विधानसभा सीट पर निगाह

कुछ महीने पहले तक चुनाव से अनिच्छुक लग रहे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अब लोगों को साधने के लिए हफ्ते में चार दिन

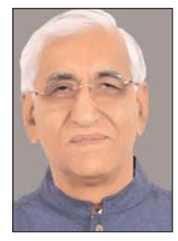

अंबिकापुर में रहने और बाकी तीन दिन सरकारी कामकाज के साथ दौरे पर रहने की बात करने लगे हैं। 2008 से लगातार अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव के फार्मूले का लोग तरह-तरह के मायने निकालने लगे हैं। कहते हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव की रणनीति बदल गई है। चर्चा है कि भाजपा इस बार वहां किसी आदिवासी चेहरा को मैदान में उतार सकती है। 2008 से पहले अंबिकापुर से कमलभान सिंह विधायक थे। भाजपा तीन बार से टीएस सिंहदेव के खिलाफ अनुराग सिंहदेव को खड़ा करते आ रही है।

भूपेश बघेल के भाषण पर नजर

छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं। चुनावी साल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को पुलिस परेड़ मैदान से प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। 15 अगस्त को भूपेश बघेल के पिटारे से क्या निकलता है, उस पर सबकी निगाह है। माना जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई घोषणाएं कर चुके हैं , लेकिन अपने इस कार्यकाल के आखिरी स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आम लोगों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों और अन्य वर्गों को क्या उपहार देते हैं,उस पर सभी की नजर है।

आखिरकार माइनिंग विभाग को मिला संचालक

2009 बैच के आईएएस केडी कुंजाम के संचालक माइनिंग बनने से इंकार के बाद खाली पड़े पद पर 2012 बैच की आईएएस दिव्या मिश्रा की पोस्टिंग की गई है। माइनिंग विभाग के सचिव 2010 बैच के आईएएस जयप्रकाश मौर्य हैं। मौर्य अभी छुट्टी पर चल रहे हैं। केडी कुंजाम ने जयप्रकाश मौर्य के मातहत काम करने से मना कर दिया था। हालांकि सरकार ने केडी कुंजाम को अब बिलासपुर संभाग का आयुक्त बना दिया है। दिव्या मिश्रा महिला और बाल विकास विभाग की भी संचालक हैं साथ में उनके पास दो प्रभार और भी हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

चुनाव की तैयारी में कार्यकर्त्ता, खिलेगा कमलः साव

■ प्रदेश एक बार फिर खुशहाली व विकास की ओर बढेगा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली व विकास की ओर बढेगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद श्री साव शनिवार को दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि एक-एक कार्यकर्ता, पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और प्रदेश की अन्यायी-अत्याचारी, वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आज भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और विश्वास है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। श्री साव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटलजी ने जिन सपनों को संजोकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, उन सपनों को साकार करने के लिए एक-एक कार्यकर्ता को साथ लेकर प्रदेश में कमल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि इस एक वर्ष में पार्टी की ओर कई बड़े-बड़े कार्यक्रम, आंदोलन किए गए हैं। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, जनता में भाजपा के प्रति विश्वास जागा है और पूरी ताकत से आज एक-एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतर चुका है। हम सब पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इस लिहाज से हम हर वह काम करेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की अन्यायी-अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिले। दिल्ली से लौटे साव, एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों और जयघोषों की गूंज के साथ भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव का शनिवार को रायपुर पहुँचने पर एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों और जयघोषों की गूंज के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्री साव को भाजपा पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएँ पहनाकर उनका अभिनंदन किया,इस दौरान एक साल बेमिसाल का केक भी कार्यकर्ताओं द्वारा कटवाया गया। हाल ही में 9 अगस्त को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने एक वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के ध्वस्त होने के बाद श्री साव शनिवार को राजधानी लौटे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेशचंद्र गुप्ता, कार्यालय सह प्रभारी रजनीश शुक्ला कार्यकर्ता उपस्थित थे।

शिव महापुराण कथा में चंदेल और नेताम पहुंचे

रायपुर। विधानसभा आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में उत्सव समिति, छत्तीसगढ़ विधान सभा के तत्वावधान में आयोजित नौ दिवसीय शिवमहापुराण कथा में पहुंचकर आज नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल और पूर्व गृह मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कथा श्रवण का पुण्य लाभ लिया एवम् पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के कृपापात्र मशहूर कथावाचक पंडित राजेन्द्र शास्त्री जी से आशीर्वाद लिया। 6 से 14 अगस्त, 2023 तक शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है, जहां प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित राजेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए अनेक गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन एवम विधान सभा के आसपास स्थित ग्रामों के श्रद्धालुजन प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं।

अपनी ही सीट से लड़ूंगा चुनाव, सभी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार तयः पांडेय

भिलाई। विधानसभा चुनाव के आते ही अब सभी राजनीतिक दल ताल ठोकने लगे हैं। पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि मैं अपने ही विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव सहित सभी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार होगी। भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय ने यह भी कहा कि कांग्रेस से अलग हुए अरविंद नेताम की पार्टी को विधानसभा में फायदा मिलेगा। तो वहीं आदिवासी दिग्गज नेताओं के अपने राष्ट्रीय पार्टियों से मोह भंग होने पर उन्होंने कहा कि नंदकुमार साय ने नमक न खाने की कसम खाई थी अब कहां जाकर बैठे हैं।

दरअसल आज जिला भाजपा कार्यलय में प्रधानमंत्री के 9 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें किसानों के लिए किए गए हितकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को फायदा हुआ और वहीं राज्य सरकार के द्वारा

किसानों को छलने का आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा के दौरान भिलाई नगर से सीट बदलकर दूसरे विधानसभा में चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि वे अपने ही विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जबकि उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का नाम लेते हुए सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को हारने की बात कही है। वहीं टाउनशिप में हाफ बिजली बिल पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि भिलाई प्रदेश सरकार के उर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर टाउनशिप में 1 सितंबर 2023 से हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आदिवासी नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया सीएम नेः नेताम

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सर्व आदीवासी समाज समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद सर्व आदिवासी समाज के आयोजन में पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम शामिल होने पहुंचे।

उन्होंने नई पार्टी बनाए जाने के सवालों पर कहा कि अब युवाओं को, नई पीढ़ी को जागरूक होना है और जल जंगल जमीन संसाधन जो खत्म हो रहे हैं उसके लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। जो आदिवासियों और मूल निवासियों के हित में बात करेगा उसी का शासन होगा। जब मीडिया ने पूछा कि कांग्रेस में वरिष्ठ मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज के हैं तो उन्होंने सीधे-सीधे आदिवासी कांग्रेस के नेताओं को सरकार के दलाल बताया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनको कुछ भी बोलने से मना किया है। मुख्यमंत्री भी समाज के नाम पर दलाली करने उतरे हुए हैं।सर्व आदिवासी समाज के आयोजन में बालोद जिला सहित आसपास के आदिवासी एवं सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने अरविंद नेताम के समर्थन में कहा कि हमारे बुजुर्ग जो बोलेंगे वह हम करेंगे और जो भी मूल आदिवासियों मोर छत्तीसगढ़ के निवासियों के हित में बात करेगा।

कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस के आगे भाजपा शून्यः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सरकार के काम और कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस के आगे भाजपा प्रदेश में शून्य हो गई है। तभी तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं से किनारा कर लिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा को बार-

बार छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। जनता 2018 से प्रदेश में भाजपा को खारिज कर रही है जनता एवं अपने केंद्रीय नेताओं का विश्वास खो चुके भाजपा नेता किस मुंह से कांग्रेस के विधायकों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे है? कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं के पसीने छूट रहे हैं और 2023 में भाजपा प्रदेश में वर्तमान की 13 सीट बचाने संघर्ष कर रही है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा का जन विरोधी चेहरा और हम दो हमारे दो की नीति देश का बच्चा-बच्चा समझ चुका है भाजपा का एकमात्र सूत्र चुनाव में जनता से वादा करना और सत्ता मिलने के बाद वादा खिलाफी करना है 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने और 9 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता से किये वादों को पूरा नहीं किया है भाजपा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जनता से किये वादा को कैसे पूरा किया जाता है।

साव विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहेंः आनंद शुक्ला

रायपुर। भाजपा के अध्यक्ष अरूण साव के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अंततः उन्होंने एक वर्ष कार्यकाल पूरा कर ही लिया उनको शुभकामनायें, लेकिन इस

एक साल में जनता का तो छोड़िये अरूण साव भाजपा के कार्यकताओं का भी भरोसा नहीं जीत पाये, भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व भी उनके नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नही कर पा रहा है यही कारण है कि छोटी-छोटी समितियों को बनाने के लिये स्वंय अमित शाह और ओम माथुर को बैठना पड़ता है अमित शाह को भाजपा के नियमित संगठनिक कार्यो को पूरा करने चुनाव तैयारियों की बैठक लेने हर हफ्ते छत्तीसगढ़ आना पड़ता है। भाजपा अपने अरूण साव को अपना चेहरा मानने तक से इंकार करती है। अरूण साव को विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है न उनका शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा कर रहा है और न ही राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है और न ही भाजपा के कार्यकर्ता उन पर भरोसा करने को तैयार है ऐसे में अरूण साव भाजपा के बेचारे अध्यक्ष साबित हो रहे है। सिवाय मोदी की चाटुकारिता के उनके पास कोई काम नही बचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनकी सरकार की योजनाओं के सामने छत्तीसगढ़ में भाजपा के सारे नेता बौने साबित हो गये है।

महिलाओं की मेहनत पर भूपेश का महिमामंडन : रंजना साहू

रायपुर। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी समाचार में महिला स्वसहायता समहों की उपलब्धियों का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए

उनकी मेहनत और उपलब्धियों से अभिभूत है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समूहों को प्रोत्साहित करने, संबल देने का अभियान भाजपा सरकार की देन है। भाजपा की सरकार ने लगातार महिला स्वसहायता समूहों को समृद्ध किया। जिसका लाभ प्रदेश की माताओं बहनों बहू बेटियों को मिला। भाजपा की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। इसके विपरीत भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं का हक छीना है। मिड डे मील का काम देखने वाली स्वसहायता समूह की 20 हजार बहनों से उनकी रोजी रोटी छीनने का पाप किया है। इसके बावजूद निर्जज्जता की हद यह है कि महिलाओं की मेहनत पर भूपेश बघेल का महिमामंडन किया जा रहा है। नकारा सरकार के प्रचारतंत्र के पास अब यही काम रह गया है। उसके पास भूपेश बघेल सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि यह सरकार ऐसा कोई काम करती ही नहीं है। मजबूरी में सरकारी प्रचार तंत्र महिला स्व सहायता समूह की बहनों की उपलब्धि का श्रेय कर्महीन मुख्यमंत्री को दे रहा है। इस सरकार में यह स्थिति है कि सरकारी प्रचार तंत्र के पास सरकार के काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है।

भूपेश सरकार ने 36 में से एक वादा भी पूरा नहीं कियाः शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की मार्कशीट आ गई है जिसमें अधिकतर को जीरो नंबर मिला है और यह हम नहीं, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में मीडिया में पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस

सिंहदेव के बयान पूरे प्रदेश ने पढ़ा और सुना है। शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के फेल्योर का बड़ा घाटा प्रदेश की जनता को हुआ है, यह बड़ा मसला है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी उपस्थित थे। शर्मा ने कहा कि जितनी बड़ी सरकार होती है, उतनी ही बड़ी एंटी इन्कम्बेंसी होती है और एंटी इन्कम्बेंसी तब और बढ़ जाती है, जब अकर्मण्य विधायक होते हैं। कांग्रेस के अधिकांश विधायक विफल सिद्ध हो गए हैं और आने वाले चुनाव में यह बात सिद्ध हो जाएगी। अभी हाल ही में अनिच्छापूर्वक उपमुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रहा है। यह बात केवल उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने ही नहीं कही, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री बघेल ने भी अपने एक बयान में कहा था कि विधायकों को बदला जाएगा, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है।

बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, भविष्य को देंगे आकार : न्यायमूर्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किशोर न्याय कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडेमी के सहयोग से उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में आयोजित विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के अपराध निवारण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, परिवर्तन एवं उनके निरोध के विकल्प विषय पर आयोजित 8वें राज्य स्तरीय कन्सलटेशन के शुभारम्भ समारोह को मुख्य आतिथ्य से सम्बोधित करते हुये मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, जो देश के भविष्य को आकार देंगे। समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में हमें उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि किशोरों को अपराध करने से रोकना समाज में अपराध की रोकथाम का एक अनिवार्य हिस्सा है तथा पुनर्वास प्रक्रिया इतनी ठोस हो सकती है कि उन्हें दोबारा विधि के साथ संघर्ष में आने से रोका जा सके। राज्य की भूमिका उस बच्चे के माता-पिता के रूप में कार्य करना है जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है तथा इसकी कार्यवाही बच्चे के सर्वोत्तम हित में होनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रारंभ से ही नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा देना आवश्यक है। बाल संरक्षण गृहों में भी यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को समाज का उपयोगी सदस्य और देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करें। उन्होने आशा तथा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आज का परामर्श कार्यक्रम बेहद सफल होगा और बच्चों के लिए एक हिंसा मुक्त समाज की स्थापना तथा प्रचार-प्रसार में काफी सहायता मिलेगी, जहां वे अपने बचपन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में हमें अथक प्रयास की आवश्यकता है। हमें बाल अपराधियों की मानसिक स्थिति को समझना चाहिये। बच्चे भगवान के उपहार हैं। उनको सही दिशा देकर समाज में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। ईश्वर की असीम कृपा से हम इतने काबिल हैं कि हमें उन बच्चों की प्रगति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने कहा कि भारत देश का भविष्य आज के बच्चे ही हैं। अतः उनके भविष्य के लिए हमें अथक प्रयास करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

खेती के लिए गंगरेल से पानी देने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर । जिले में अभी बरसात थमे एक सप्ताह भी बीता नहीं है कि गंगरेल से डिस्चार्ज बढ़ाने की मांग शुरू हो गया है । बीते कल अभनपुर क्षेत्र के विधायक व पूर्व सिंचाई मंत्री धनेन्द्र साहू द्वारा मांगकिये? जाने के बाद आज बंगोली सिंचाई उपसंभाग के अधीन आने वाले सिंचाई पंचायतों के पूर्व अध्यक्षों व सरपंचोंने सिंचाई पानी की आवश्यकता के मद्देनजर गंगरेल से डिस्चार्ज बढ़वाने की मांग जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे से की है।

ज्ञातव्य हो कि इस वर्ष असमान वर्षा के चलते किसानों को खरीफ खेती में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । अत्यधिक बरसात वाले क्षेत्र में किसानों को दोबारा - तिबारा बोनी करना पड़ रहा है तो रोपाई व धान के चलाई में भी तकलीफ हो रही है । खेती का खर्च इस शुरूआती दौर में ही बढ़ गया है । कम वर्षा वाले क्षेत्र के? किसानों की मांग पर गंगरेल का पट पहले ही खोला जा चुका है पर अब अत्यधिक बरसात की वजह से रोपाई व चलाई कार्य के चलते खेत में पानी जमा न रख पाने के लिये विवश किसान भी बीते एक सप्ताह से बरसात थम पाने की वजह से खेती के लिये सामयिक पानी की आवश्यकता को देखते हुये गंगरेल से महानदी मुख्य नहर में पानी का डिस्चार्ज बढ़ाने की मांग करने लगे हैं । किसानों की मांग के परिपेक्ष्य में सिंचाई पंचायतों के पूर्व अध्यक्षों व पंचायत प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श पश्चात गंगरेल से पानी का डिस्चार्ज बढ़वाने की मांग करने का निर्णय ले जल संसाधन मंत्री श्री चौबे से गंगरेल से पर्याप्त डिस्चार्ज बढ़वाने की मांग की है । सिंचाई पंचायत के अध्यक्ष रहे गोविंद चंद्राकर , थानसिह साहू , हिरेश चंद्राकर , प्रहलाद चंद्राकर , धनीराम साहू , भारतेन्दु साहू , तुलाराम चंद्राकर , चिंताराम वर्मा , योगेश चंद्राकर , मनम?ोहन गुप्ता , भूपेन्द्र शर्मा आदि सहित सरपंच नंदकुमार यादव मौजूद थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.